फाल्गुन शुक्ल पक्ष- प्रतिपदा, 2082 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-09, अंक - 225 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म।प्र।/4-474/2024-26

भोपाल
18 फरवरी 2026 बुधवार

आज का मौसम
30.3 अधिकतम
15.6 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

जगदीश देवड़ा ने पेश किया 4.7 लाख करोड़ का बजट

मोहन यादव सरकार के तीसरे बजट में कुछ खास वर्गों का ध्यान रखा गया है जिसमें युवा, किसान और महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश की 15 से 29 वर्ष की युवा आबादी पर सरकार का फोकस है। लाड़ली बहनों को दी जा रही मासिक सहायता राशि के लिए भारी भरकम प्रावधान किया गया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकार अब तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन देगी।

युवाओं, किसान और महिलाओं की उम्मीदों पर नजर

हृदय प्रदेश का विकास पथ

भोपाल, दोपहर मेट्रो

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट था। इस बजट में खासतौर से युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस किया गया है। देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। उन्होंने एक लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने कहा कि हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है। लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान है। वहीं बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में हंगामा और नारेबाजी की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत होकर अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए।

युवा प्रदेश के लिए

मध्य प्रदेश खुद को देश के 'युवा प्रदेश' के रूप में स्थापित कर रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि 'उद्यम क्रांति योजना' के माध्यम से अब तक 16,451 युवाओं को लोन दिया जा चुका है। प्रदेश में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। पिछले 2 वर्षों में राज्य को 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगे।

सिंहस्थ के लिए

उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ के लिए सरकार ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। चूंकि केंद्र सरकार के बजट में इसके लिए अलग से राशि नहीं मिली थी, इसलिए राज्य सरकार ने अपने बजट में इसके लिए 13851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

7 लाख 95 हजार छात्रों को सहायता

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है।

सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़

20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए 12,690 करोड़ का प्रावधान। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए 'संध्या छाया' प्रोग्राम। उन बुजुर्गों के लिए जो एकाकी जीवन जी रहे हैं या जिनके बच्चे दूर रहते हैं।

नारी कल्याण के लिए सवा लाख करोड़

पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए 80 लाख दूध पैकेट का वितरण। इसके लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रावधान। कामकाजी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में 'सखी भवन' का निर्माण। नारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ ।

किसको क्या मिला

लाड़ली बहनें

लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ की भारी-भरकम राशि आवंटित। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं।

श्रमिक हित

असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग के बजट में 1,335 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। इसे अधिकारों की सुरक्षा और सहायता योजनाओं पर खर्च करेंगे।

किसान कल्याण

3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत किया गया है।

मत्स्य उत्पादन

मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में 412 करोड़ के निवेश का प्रावधान । मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

यह बजट गरीब-युवा-अन्नदाता और महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को समर्पित है।

– डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

भाजपा को सिर्फ सपने दिखाने की पुरानी आदत है, और यह बजट भी उसी दिशा में एक कदम है। आम जनता को कुछ नहीं मिला

– उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

खास मदों में बजट आवंटन

जीरामजी योजना	-	10440
पीएम आवास योजना	-	6850
स्वच्छ भारत मिशन	-	400
पुलिस विभाग	-	14306
सीएम तीर्थ दर्शन योजना	-	50
पीएम जनमन योजना	-	900
छात्रवृत्ति	-	286
धरती आबा योजना	-	752
लोक निर्माण	-	12690

(राशि करोड़ रुपए में)

50 हजार पदों पर भर्ती

करीब 15,000 शिक्षकों की भर्ती का एलान किया गया है जो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर युवाओं के लिए 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है।

जी रामजी योजनाः धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए 10,428 करोड़ रुपये का प्रावधान। यह योजना मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक संरक्षण पर केंद्रित है।

किसानों को 25 हजार करोड़ का अल्पकालीन ऋण

बजट में पशुपालन के लिए 2364 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण दिलाया जाएगा। बिना ब्याज का ऋण दिलाने के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। भावांतर योजना के तहत किसानों को 337 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। एमपी देश का तीसरा युवा प्रदेश, यहां 28 प्रतिशत युवा हैं।

आज का कार्टून

दस राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित, वोटिंग 16 मार्च को

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव की घोषणा की है। मतदान की तिथि 16 मार्च 2026 है और मतगणना मतदान के दिन ही होगी। बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार की खाली हो रही राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक ये सीटें अप्रैल महीने में अलग-अलग तारीखों को खाली हो रही हैं। राज्यसभा का कार्यकाल छह साल का होता है। लेकिन हर एक तिहाई सीटों के लिए हर दो साल पर द्विवार्षिक चुनाव कराए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसे स्थाई सदन कहा जाता है।

प्रदेश में बदला मौसम, रतलाम में बारिश, 22 जिलों के लिए अलर्ट

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश के 22 जिलों में आज को आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट है। इनमें इंदौर, ग्वालियर-उज्जैन भी शामिल हैं। रतलाम जिले के अलग-अलग इलाकों में मंगलवार रात बारिश हुई। दो साइक्लोनिक चक्रवात और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम बदलेगा। गुरुवार को भी ग्वालियर-चंबल में बारिश होने का अनुमान है। जिन जिलों में बारिश होने के आसार हैं, उनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, आलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल हैं।

आज भारत का आखिरी ग्रुप मैच नीदरलैंड से

नईदिल्ली, एजेंसी

टी-20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ होगा। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया ने पहले ही सुपर-8 स्टेज में एंट्री कर ली है। हालांकि, टी-20 के नंबर-1 बैटर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक खाता भी नहीं खोल सके हैं।

रोबोटिक डॉग बनाने का झूठा दावा

गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई इम्पैक्ट समिट से बाहर किया

नई दिल्ली, एजेंसी

नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को नई दिल्ली में चल रही एआई समिट के एक्सपो एरिया से बाहर कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है। यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज रोबोटिक डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह दिख रही हैं। वे कह रही हैं कि इस रोबोटिक डॉग का नाम 'ओरियन' है और इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने तैयार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह मशीन निगरानी और

मॉनिटरिंग करने में सक्षम है और कैंपस में कहीं भी घूम सकती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि यह असल में चीनी कंपनी यूनिट्री का गो मॉडल है, जो बाजार में 2-3 लाख रुपए में उपलब्ध है। वीडियो वायरल होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा- हमने लगातार कैंपस में बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है। जब छात्र नई चीजें देखते हैं, तभी उनकी सोच विकसित होती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का विवादास्पद फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पायजामे का नाड़ा खोलना भी रेप का प्रयास

नई दिल्ली, एजेंसी

किसी महिला को गलत तरीके से छूना और उसके पायजामे की डोरी खोलना रेप का प्रयास माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें इस अपराध को प्रयास नहीं बल्कि रेप की तैयारी बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रियाओं में संवेदनशीलता लाने के लिए समिति को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले साल मार्च में आए फैसले पर काफी हंगामा मचा था। इसमें उसने कहा था कि पायजामे का नाडा खोलने से यह नहीं कहा जा सकता कि यह रेप की कोशिश है। वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता के एक लेटर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद

इस मामले पर संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत , जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर पॉक्सो एक्ट के तहत दो आरोपियों पर रेप की कोशिश का आरोप फिर से लगा दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने फैसले में लिखा कि जजों को सिर्फ संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों को सही ढंग से लागू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि दया और सहानुभूति का माहौल भी बनाना चाहिए।

कूनो से फिर आई अच्छी खबर

अफ्रीकी चीता 'गामिनी' दूसरी बार मां बनी, 3 शावकों को दिया जन्म

श्योपुर, एजेंसी

कूनो नेशनल पार्क से एक और अच्छी खबर आई है। दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आने के 3 साल पूरे होने के मौके पर, कुनो में तीन नए शावकों का जन्म हुआ है। यह भारत में चीतों के लिए एक नई और शानदार शुरुआत है। चीता गामिनी ने तीन शावकों को जन्म दिया है। यह भारत में चीतों के लिए नौवां सफल जन्म है। गामिनी दूसरी बार मां बनी है। इससे पहले इसी महीने, नामीबिया से भारत लाई गई चीता 'आशा' ने कूनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को जन्म दिया था।

इन नए शावकों के साथ, भारत में जीवित भारतीय मूल के चीतों की संख्या 27 हो गई है। गामिनी को भारत से दक्षिण अफ्रीका के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के

तहत लाया गया था। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2022 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में दुनिया के सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाले जानवर की आबादी को फिर से स्थापित करना था, जो दशकों पहले विलुप्त हो गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कूनो में तीन नए शावकों का स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आगमन के 3 साल पूरे होने के अवसर पर कूनो में एक शानदार नया अध्याय।

हादसों का हॉटस्पॉट... सड़कों पर बैठे मवेशी बढ़ा रहे खतरा

भोपाल के छोला रोड और जेपी नगर रोड पर नगर निगम की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। बीते कई दिनों से इन व्यस्त सड़कों पर सुबह-शाम गाय व अन्य मवेशी बीच सड़क पर बैठे रहते हैं, लेकिन इन्हें हटाने या स्थायी समाधान की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मवेशियों के कारण वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे होते-होते बचे हैं। खासकर दोपहिया वाहन चालक और स्कूली वाहन सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं। स्थिति यह है कि थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसके साथ ही सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े से आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल बसें और एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती हैं, लेकिन नगर निगम और संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? अब जरूरत है कि नगर निगम तुरंत मवेशियों को पकड़ने की नियमित कार्रवाई करे, गौशालाओं की व्यवस्था दुरुस्त करे और सड़कों को सुरक्षित बनाए, ताकि आम नागरिकों की जान जोखिम में न पड़े।

ताकि भीड़ नियंत्रण या फोर्स मूववमेंट में दिक्कत आई न आए

पूरे प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों की डिजिटल घेराबंदी करा रही है पुलिस

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

पुलिस अपराध, दुर्घटना और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों की डिजिटल घेराबंदी करा रही है। यह काम जिओ टैगिंग के जरिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम की जीआईएस (जियोग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम) यूनिट मध्य प्रदेश के 35 प्रमुख जिलों में यह काम कर रही है। प्रदेश भर में 1314 स्थान चिह्नित कर उन्हें जिओ टैग किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इस तकनीकी कदम से पुलिस की अपराध नियंत्रण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और निगरानी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। अब तक पुलिस के पास संवेदनशील इलाकों की सूची तो थी, लेकिन मौके पर पहुंचने के लिए सटीक डिजिटल नक्शा और वैकल्पिक मार्गों की स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। कई बार संकरी गलियों, अवैध निर्माण और बंद रास्तों के कारण दूसरे क्षेत्रों से बुलाई गई फोर्स को अंदर तक पहुंचाने में समय लगता था। राजधानी में भी पुलिस ने 32 थानों के 100 से अधिक चिह्नित संवेदनशील इलाकों की जियो टैगिंग का काम पूरा कर लिया गया है। हर थाने के अंतर्गत तीन से चार ऐसे क्षेत्रों को जीआईएस से टैग किया गया है, जहां पूर्व में तनाव, भीड़ नियंत्रण या फोर्स की मूवमेंट में दिक्कतें सामने आई थी।

एमपी जियो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा

नई व्यवस्था के तहत जीआईएस यूनिट हर लोकेशन का विस्तृत डिजिटल मैप तैयार कर रही है। इसमें मुख्य प्रवेश मार्ग, वैकल्पिक रास्ते, संभावित बाधाएं, भीड़ जमा होने के स्थान और फोर्स के फंसने की आशंका वाले स्थलों को अलग-अलग मार्क किया गया है। पूरा डाटा तैयार होने के बाद इसे एमपी जियो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जहां से पुलिस अधिकारी लाइव लोकेशन देख सकेंगे। इस सिस्टम से कंट्रोल रूम से ही संबंधित थाना प्रभारी या जोनल अधिकारी को सटीक दिशा-निर्देश दिए जा सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सीहोर सहित करीब 20 जिलों में काम पूरा हो चुका है। अन्य जिलों में काम अंतिम चरण में है।

इस तरह काम करेगा यह सिस्टम

जियो टैगिंग और मैपिंग - पुलिस और जीआईएस यूनिट मौके पर जाकर लोकेशन का सर्वे करती है।

डिजिटल लेयर - मुख्य मार्ग, संवेदनशील प्वाइंट, वैकल्पिक मार्ग व संभावित बाधाएं लेयर में मार्क होंगी।

डाटा अपलोड - पूरा मैप एमपी जियो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

लाइव एक्सेस - पुलिस कंट्रोल रूम व अधिकारियों को यूजर आईडी-पासवर्ड मिलेगा, जिससे मैप देख सकेंगे।

ऑपरेशन प्लानिंग - किसी भी आपात स्थिति में फोर्स की एंट्री, निकासी और बैकअप रूट पहले से तय रहेंगे।

खाली मैदानों में डंप हो रहा कचरा

राजधानी में अघोषित 'कचरा खंती' बना रहा नगर निगम

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राजधानी को स्वच्छता में अव्वल बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाला नगर निगम प्रशासन अब खुद ही शहर की सफाई व्यवस्था को पलीता लगाने पर तुला है। शहर के विभिन्न वार्डों से कचरा एकत्र करने के बाद उसे आदमपुर खंती तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निगम के अमले की है, लेकिन इस व्यवस्था में लगे कर्मचारी समय और ईंधन बचाने के शार्टकट अपना रहे हैं। कचरा वाहनों को खंती तक ले जाने के बजाय शहर के अंदर ही खाली मैदानों में कचरा खाली किया जा रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों के पास अघोषित डंपिंग साइट्स बनती जा रही हैं।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास

सफाई अमले की इस बड़ी लापरवाही का प्रत्यक्ष प्रमाण सब्जी मंडी के पास बने छोला फ्लाईओवर के नीचे देखा जा सकता है। नगर निगम के कर्मचारी करोंद सब्जी मंडी, प्रीत नगर, आरिफ नगर, शिवनगर जैसे क्षेत्रों में घर-घर जाकर कचरा एकत्रित करते हैं, लेकिन उस कचरे को आदमपुर खंती तक नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे छोला फ्लाइओवर के पास खाली पड़े मैदान में डाल दिया जाता है। इससे वहां पर कचरे का ढेर लग गया है। इस अघोषित खंती के कारण पूरे क्षेत्र में भारी दुर्गंध फैल रही है, जिससे स्थानीय निवासियों और यहां

से गुजरने वाले राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है।

नियमों को ताक पर रखकर हो रहा कार्य

रिहायशी इलाकों के करीब इस तरह कचरा डंप होने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नियमानुसार कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन होना चाहिए, लेकिन खुले में कचरा फेंकने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आवारा पशुओं का जमावड़ा भी लग रहा है। इस गंभीर लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं।

दाऊदी बोहरा समाज के लिए रमजान-उल-मुबारक शुरू

सुन्नी समाज को आज चांद दिखने की उम्मीद

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने मंगलवार से रमजान-उल-मुबारक का आगाज़ सादगी, अनुशासन और इबादत के माहौल में किया है। यह पवित्र महीना 18 मार्च तक चलेगा। सुबह से ही मस्जिदों और घरों में इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। समाजजनों ने रोजे रखकर अमन, भाईचारे और देश-दुनिया की खुशहाली के लिए दुआ की।

दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में दुनिया भर के साथ-साथ भोपाल के बोहरा समाज ने भी रमजान का स्वागत किया। समुदाय के लोगों ने बताया कि यह महीना आत्मसंयम, आध्यात्मिक उन्नति और जरूरतमंदों की मदद का संदेश देता है। रोजा भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि

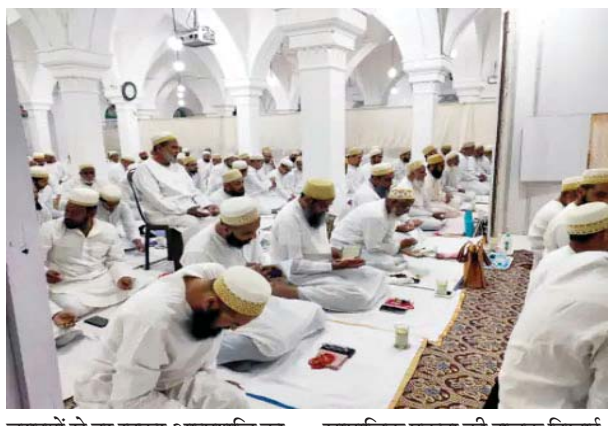

बुराइयों से दूर रहकर आत्मशुद्धि का माध्यम है। मस्जिदों में विशेष नमाज और कुरआन-ए-पाक की तिलावत का दौर शुरू हो गया है। समाज की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इफ्तार के दौरान सामूहिक रूप से रोजा खोला जाएगा, जिसमें सामाजिक एकता की झलक दिखाई देगी। सुन्नी समुदाय में रमजान की शुरुआत चांद दिखने पर निर्भर करती है। 18 फरवरी को चांद नजर आने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि चांद दिखाई देता है तो 19 फरवरी से सुन्नी समुदाय में भी रमजान शुरू हो जाएगा।

सड़क सुरक्षा पर मंथन; तेज गति, ओवरटेकिंग और लापरवाही हादसे के कारण

डीसीपी बोले- 15 साल में ट्रैफिक 10 गुना बढ़ा

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

15 सालों में शहर का ट्रैफिक लगभग 10 गुना बढ़ गया है जबकि सड़कों का विस्तार उसी अनुपात में नहीं हुआ। यह स्थिति यातायात प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। जागरूकता ही सुरक्षा का मूल मंत्र है। नागरिकों के सहयोग से ही दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं।

यह कहना है यातायात डीसीपी जितेंद्र सिंह पंवार का। वे भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता विषय पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य अस्पताल के कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित यातायात व्यवहार को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसीपी (यातायात) देवेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। डीसीपी पंवार ने कहा कि भारत में सर्वाधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती हैं।

इसके पीछे यातायात नियमों की अनदेखी और जागरूकता का अभाव प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शहरों में जनसंख्या और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन सड़क ढांचा उतनी गति से विकसित नहीं हुआ। ऐसे में नागरिकों का अनुशासित व्यवहार ही दुर्घटनाओं को कम कर सकता है।

युवाओं पर अधिक खतरा: एसीपी देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में 90 प्रतिशत लोग 20 से 45 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। तेज गति, खतरनाक ओवरटेकिंग और लापरवाही से वाहन चलाना दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने सलाह दी कि वाहन चलाने से पहले टायरों की हवा और ब्रेक की स्थिति की जांच अवश्य करें। सड़क पर वाहन चलाते समय अहंकार नहीं, बल्कि संयम और धैर्य जरूरी है।

मेट्रो एंकर | स्टूडेंट्स को मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए सुझाव, दबाव नहीं बना सकेंगे संचालक

कोचिंग सेंटर्स के लिए नियम बनाएगी सरकार

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने और विद्यार्थियों की आत्महत्या की रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए राज्य सरकार नए नियम बनाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक करके सुझाव मांगे हैं और विद्यार्थियों के मानसिक दबाव से उत्पन्न होने वाली गंभीर परिस्थितियों को रोकने के नियम सबके सुझावों पर मंथन के बाद जारी किए जाएंगे। सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में कोचिंग संस्थानों के नियमों को लेकर हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग अनुपम राजन और कोचिंग संचालकों के बीच संवाद हुआ। यह संवाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए तय की जाने वाली व्यवस्था के अंतर्गत किए गए। इसमें कोचिंग सेंटरों के लिए नियम तैयार कर उसे नोटिफाइ कर लागू किया जाएगा।

सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराएं

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने विद्यार्थियों, बैठक में शामिल करने वाले विभागों के प्रतिनिधियों, कोचिंग सेंटर संचालकों एवं समिति सदस्यों से सुझाव लिए। एसीएस राजन ने कहा कि विद्यार्थियों में बढ़ती मानसिक दबाव की स्थिति को गंभीरता से समझते हुए घटनाओं की प्रभावी रोकथाम आवश्यक है। कोचिंग संस्थानों को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और विद्यार्थियों को सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार विद्यार्थी जीवन की चुनौतियों और मानसिक समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, जिसके कारण गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए सभी संबंधित संस्थाओं के सहयोग से विद्यार्थियों के हित में एक प्रभावी नि?यम तैयार किया जाना है, जिससे मानसिक दबाव से उत्पन्न होने वाली गंभीर परिस्थितियों को रोकने में मदद मिल सके।

हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना जरूरी

अपर मुख्य सचिव राजन ने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाएं। साथ ही व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए। बैठक के दौरान राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण, बेहतर संचालन, निर्धारित मानकों का पालन, कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित वातावरण, पारदर्शी शुल्क व्यवस्था, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए एक समयबद्ध और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर चर्चा की गई।

आलोक शर्मा ने दिए 10 लाख, समाज भवन में कक्ष निर्माण का भूमिपूजन

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवानदास सबनानी ने कोटरा स्थित कमला नगर थाने के पास हलवा-हलवी समाज भवन में विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन किया। हलवा हलवी समाज भवन में कक्ष निर्माण कार्य के लिए सांसद आलोक शर्मा ने अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। अब भूमिपूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने से समाज को इसका फायदा होगा। हलवा-हलवी समाज ने सांसद आलोक शर्मा का आभार व्यक्त किया है।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकाय के छात्र-छात्राओं को उपाधियां और पदक प्रदान किए। साथ उन्हें संबोधित किया।

इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा

3000 से ज्यादा लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ाने की तैयारी 10% से ज्यादा हो सकती है वृद्धि

इंदौर, दोपहर मेट्रो

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले में संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन से मिले ऑनलाइन डाटा और स्थानीय स्तर पर किए गए आकलन के आधार पर गाइडलाइन दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिले में तीन हजार से अधिक लोकेशन पर बढ़ोतरी हो सकती है। इस माह उप पंजीयन कार्यालय में प्रस्ताव तैयार कर जिला मूल्यांकन समिति में पहुंचेगा। यहाँ से स्वीकृति के बाद मार्च के मध्य में प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजना होगा।

एआई और संपदा-2 के आधार पर होगा मूल्यांकन- दरअसल, उप पंजीयन कार्यालयों में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हुए संपत्ति सौदों का विश्लेषण किया गया है। जहां जमीन या संपत्ति की खरीद-फरोख्त तय गाइडलाइन दर से अधिक कीमत पर हुई है, उन स्थानों पर दर बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। इसमें 10 प्रतिशत से ज्यादा दस्तावेज पंजीकृत होने वाली लोकेशन को ही बढ़ोतरी में शामिल किया गया है। एआई और संपदा-2 के आधार पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

हजारों लोकेशन पर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित- शासन ने बीते माह करीब 3200 लोकेशन पर संभावित बढ़ोतरी की जानकारी भेजी थी। विस्तृत जांच के बाद 2400 स्थानों पर 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी सामने आई है, जबकि करीब 600 स्थानों पर स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बीच में विभाग ने सौ से अधिक नई कालोनियों को गाइडलाइन में जोड़ने का प्रस्ताव भेजा था, जिनमें से 91 को मंजूरी मिल चुकी है। इनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर रजिस्ट्रियां भी शुरू कर दी गई।

नई लोकेशन और पिछले वर्षों का रिकॉर्ड

आने वाले वित्तीय वर्ष में करीब 200 नई लोकेशन और शामिल होने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं, जिनमें स्वीकृत नक्शा, रेरा पंजीयन और अन्य वैध अनुमतियां जरूरी होंगी। मौजूदा वित्त वर्ष में भी कई क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में 20 से लेकर 270 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी। सबसे ज्यादा वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि में देखी गई थी। अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां होने और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए गए थे।

विधानसभा में आया जवाब, कोविड के रोजगार की मांग बढ़ी, पर हाथ खाली

6 साल में एक फीसदी मजदूरों को भी नहीं मिला 100 दिन काम, 150 दिन रोजगार का दावा भी अधूरा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश में मनरेगा के तहत पिछले छह वर्षों में 1 प्रतिशत मजदूरों को भी पूरे 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया। यह खुलासा विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में हुआ। जवाब में सामने आया कि बड़ी संख्या में मजदूर पंजीकृत होने के बावजूद सीमित परिवारों को ही 100 दिन का काम मिला। विधानसभा में दिए गए जवाब के अनुसार वर्ष 2021 में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक पंजीकृत मजदूरों में से केवल 1 लाख 23 हजार परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिला। वर्ष 2022 में यह संख्या घटकर 63 हजार 898 परिवार, वर्ष 2023 में 40 हजार 588, वर्ष 2024 में 30 हजार 420 और वर्ष 2025 में 32 हजार 560 परिवार रह गई। आंकड़ों के आधार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि छह वर्षों में 1 प्रतिशत मजदूरों को भी पूरा रोजगार नहीं मिल सका।

मनरेगा के तहत वनाधिकार पट्टाधारियों को वर्ष में 150 दिन रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 में 24 जिलों में एक भी मजदूर को 150 दिन का रोजगार नहीं मिला। चार जिलों में मात्र एक-एक परिवार को ही 150 दिन काम दिया गया। जानकारी में बताया गया कि सबसे अधिक अलीराजपुर जिले में 112 परिवारों को 150 दिन रोजगार मिला, जबकि छिंदवाड़ा में 28, धार में 21, मंडला में 17 और दमोह में 16 परिवारों को यह लाभ मिला। आदिवासी जिला झाबुआ में 150 दिन रोजगार का आंकड़ा शून्य रहा।

मजदूरी की मांग बढ़ी, रोजगार नहीं

विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कोविड काल के बाद से मजदूरी की मांग लगातार बढ़ी, लेकिन रोजगार उपलब्धता उसी अनुपात में नहीं बढ़ सकी। बड़ी संख्या में परिवारों और श्रमिकों ने काम की मांग की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर सवाल खड़े हुए हैं।

जॉब कार्डधारी परिवार बढ़े, काम कम मिला

प्रदेश में जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रति परिवार मिलने वाले कार्य दिवस घटे हैं। विपक्ष ने इसे सरकार की रोजगार नीति की विफलता बताते हुए कहा कि ग्रामीण मजदूरों को पर्याप्त काम नहीं मिल पाने के कारण पलायन की स्थिति बन रही है।

साल	पंजीकृत मजदूर	100 दिन रोजगार पाने वाले परिवार
2021	1,70,19,681	1,23,624
2022	1,81,42,207	63,898
2023	1,69,07,207	40,588
2024	1,70,42,207	30,420
2025	1,86,57,080	32,560

रोजगार की मांग के बीच बाहर हुए मजदूर

आंकड़ों के मुताबिक कोविड के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग लगातार बढ़ी, लेकिन उसी दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम जॉब कार्ड से हटाए जाने से मजदूरों को काम पाने में कठिनाई हुई।

विपक्ष का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब ग्रामीण मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत थी, उसी समय नाम काटे जाने से उन्हें काम से वंचित होना पड़ा और पलायन की स्थिति बनी। विधानसभा में सामने आए इन आंकड़ों के बाद मनरेगा के क्रियान्वयन और जॉब कार्ड सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।

मजदूरी की मांग भी रही ऊंची

वर्ष	परिवार	श्रमिक
2021-22	61,66,780	1,21,95,233
2022-23	53,13,454	92,99,519
2023-24	46,99,747	76,31,549
2024-25	44,79,776	69,86,086
2025-26	42,64,414	65,47,787

150 दिन रोजगार का प्रावधान भी अधूरा

मनरेगा के तहत वनाधिकार पट्टाधारियों को वर्ष में 150 दिन रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन 2025-26 में स्थिति कमजोर रही।

जिलावार स्थिति (150 दिन रोजगार)

24 जिलों में — एक भी परिवार को नहीं मिला रोजगार
4 जिलों में — सिर्फ 1 परिवार को मिला रोजगार
अलीराजपुर — 112 परिवार
छिंदवाड़ा — 28 परिवार
धार — 21 परिवार
मंडला — 17 परिवार
दमोह — 16 परिवार
झाबुआ — शून्य

विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले वर्षों में लाखों परिवारों और श्रमिकों के नाम जॉब कार्ड से हटाए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नाम कोविड काल के दौरान काटे गए। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में 10 लाख 46 हजार 786 परिवारों के 43 लाख 43 हजार 378 श्रमिकों के नाम जॉब कार्ड से हटाए गए। उस समय रोजगार की मांग सबसे अधिक थी, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर योजना से बाहर हो गए।

राज्य मंत्री पवार ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

अगले 2 वर्षों में प्रदेश का मछली उत्पादन दोगुना करने का तय हुआ लक्ष्य

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार ने भोपाल स्थित मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित के सभागार में विभाग की समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं आगामी कार्य योजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार आगामी 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्यमंत्री श्री पंवार ने कहा कि ÷किसान कल्याण वर्ष÷ में मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले मछुआरों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाए। राज्यमंत्री श्री पंवार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर मत्स्य महासंघ के माध्यम से मछुआरों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए तथा रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जाएं।

राज्यमंत्री श्री पंवार ने मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर को प्रोत्साहित करने के लिये ÷फार्म पॉन्ड मॉडल÷ की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया। साथ ही सहकारिता के माध्यम से मछली पालन के साथ सिंघाड़ा, कमलगट्टा एवं मखाना जैसी पूरक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, जिससे मत्स्य पालकों की आय में बहुआयामी वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। राज्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न वर्गों की 2645 मछुआ समितियां पंजीकृत हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या 1,00,197 है। प्रदेश में 4.42 लाख हैक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 99 प्रतिशत क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया जा चुका है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। मंत्री श्री पंवार ने कहा कि जिन तालाबों में 6 से 9 महीने तक पानी रहता है, वहां बोनसाई सीड के जरिए मत्स्य उत्पादन किया जाए। मत्स्य समितियों की जांच कर फर्जी और निष्क्रिय सदस्यों को हटाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि असली मछुआरों को लाभ मिल सके। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, एमडी श्री अनुराग चौधरी, डायरेक्टर श्री मनोज कुमार पथरोलिया उपस्थित रहे।

देवास में हिमालय से उड़कर पहुंचे विशाल गिद्ध

मप्र में पहली बार किंग और इंडियन वल्चर के साथ दिखी हिमालयन ग्रिफॉन की जोड़ी

देवास, दोपहर मेट्रो

हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं से हजार किलोमीटर से अधिक की उड़ान भरकर विशाल गिद्ध मध्यप्रदेश के खिवनी वन्यजीव अभयारण्य पहुंचे हैं। यहां पहली बार हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर के साथ दो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां किंग (रेड-हेडेड) वल्चर और इंडियन वल्चर एक साथ देखी गई हैं। पिछले साल से इजिप्शियन वल्चर ने भी खिवनी को अपने आवास के रूप में चुना है। जानकारों के अनुसार यह घटना केवल प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रजातियों की एक साथ मौजूदगी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है।

हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाला विशाल ग्रिफॉन गिद्ध सामान्यतः ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है। सर्दियों में भोजन की तलाश में यह मैदानी इलाकों की ओर आता है, लेकिन मध्यभारत तक पहुंचना बहुत कम दर्ज होता है। माना जा रहा है कि खिवनी का सुरक्षित वातावरण और पर्याप्त भोजन उपलब्धता इसे यहां तक खींच लाई है।

दो क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों की मौजूदगी

खिवनी में किंग वल्चर और इंडियन वल्चर भी हिमालयीन गिद्ध के अलावा दिखे हैं। दोनों प्रजातियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ÷गंभीर रूप से संकटग्रस्त÷ श्रेणी में हैं और इनकी संख्या बेहद कम बची है। शिवानी अभयारण्य अधीक्षक विकास माहोरे ने बताया कि गिद्ध प्रकृति के सफाईकर्मी हैं। यहां एक साथ इतनी प्रजाति के गिद्धों का दिखना पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं।

शावकों को शिकार करना सिखा रही बाघिन

दुर्लभ गिद्धों के साथ ही खिवनी अभ्यारण में बाघों की भी बड़ी मौजूदगी है। खिवनी की रानी बाघिन वन विभाग के ट्रैप कमरे में अपने तीन शावकों के साथ नजर आई है। इस बार बाघिन तीनों छोटे शावकों को शिकार करना सिखाते हुए दिखाई दे रही है। बता दें खिवनी में लगभग 10 बाघों की मौजूदगी है।

134 वर्ग किमी में फैला है अभयारण्य

खिवनी अभयारण्य देवास और सीहोर जिले की सीमा में लगभग 134 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घा, विभिन्न प्रजातियों के हिरण, कई प्रजातियों के सांप सहित 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी रहते हैं।

दिल्ली में लगी रहा चार साल का वक्त

बच्चों से जुड़े अपराधों में न्याय मिलने की रफ्तार हमारे प्रदेश में रही बेहतर

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले गंभीर अपराधों के मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने की रफ्तार देश के कई बड़े राज्यों और महानगरों की तुलना में काफी बेहतर है। राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (स्वञ्जस्ष्ट) में इन मामलों के ट्रायल (विचारण) में लगने वाला औसत समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों के मुकाबले काफी कम है।

एमपी में 380 दिन में फैसला, दिल्ली में साढ़े 4 साल- विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी 2024 के आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश में एक पॉक्सो मामले के निपटारे में औसतन

380 दिन का समय लगता है। इसकी तुलना यदि अन्य राज्यों से की जाए, तो तस्वीर काफी चौंकाने वाली है।

दिल्ली: यहां पॉक्सो केस के ट्रायल में औसतन 1639.5 दिन (लगभग 4.5 साल) लग रहे हैं।

गुजरात: यहां न्याय मिलने में औसतन 1292.5 दिन का समय लगता है।

उत्तर प्रदेश: यहां भी ट्रायल में औसतन 861 दिन लगते हैं, जो एमपी से दोगुने से भी अधिक है।

देशभर में 2.24 लाख से ज्यादा मामले लंबित

मंत्रालय ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉक्सो अधिनियम के तहत कुल 2,24,572 मामले लंबित थे। इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए वर्तमान में देश भर में 774 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं, जिनमें 398 विशेष तौर पर केवल पॉक्सो (ई-पॉक्सो) कोर्ट हैं। सरकार पीड़ितों को सुविधाजनक माहौल देने के लिए न्यायालय परिसरों के भीतर सुभेद्य साक्षी निक्षेपण केन्द्रों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। इसके माध्यम से बच्चों के लिए डरावने न्यायिक वातावरण के बजाय एक %चाइल्ड फ्रेंडली% माहौल तैयार किया जा रहा है।

मेट्रो एंकर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को लग रहा पलीता

शाजापुर में सात माह में ही लकड़ियों में तब्दील हुए पौधे

शाजापुर, दोपहर मेट्रो

‘एक पेड़ मां के नाम’ विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। यह पहल लोगों को अपनी मां के प्रति सम्मान और प्यार के प्रतीक के रूप में, या उनकी याद में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह कैंपेन धरती माता की रक्षा के लिए नागरिकों की भागीदारी पर केंद्रित है, लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर में इस अभियान की धरातल पर हकीकत कुछ और ही है।

प्रदेशभर में साल 2025 में जुलाई माह में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत प्रदेश सरकार ने की। मध्यप्रदेश के शाजापुर में इसके तहत पौधारोपण किया गया। शाजापुर के भैरव डूंगरी में जिला प्रशासन शाजापुर, सांसद व विधायक समेत अकई संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी और लगभग एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था।

लेकिन यहां पर 151 पौधे लगाएं गए। 151 पौधों लगाने में क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, शाजापुर विधायक अरुण भीमावद समेत भाजपा पदाधिकारी, सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय नागरिक शामिल थे। 151 पौधे भी आज जीवित अवस्था में नहीं है।

अभियान को लगाया पलीता, लाखों का किया खर्चा- जिला मुख्यालय पर 13 जुलाई 2025 को आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान को बड़े स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने आमजन से इस अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया था। जिसको लेकर स्थानीय भैरव डूंगरी पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस प्रकार की तैयारी की थी। यह तैयारी किसी शादी की तैयारियों से कम नहीं थी, जिसके चलते लाखों रुपये खर्च किये गए थे।

एक लाख की जगह 151 पौधे लगाए गए, सात महीनों में एक भी नहीं बचा

क लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 151 पौधे ही लगा पाए। जिनमें 50 पौधे भाजपा पदाधिकारी, 50 पौधे सामाजिक संस्थाओं और 50 पौधे नवयुगल ने लगाए थे, लेकिन सात माह बाद जब मीडिया ने उस जगह का मौका मुआवना किया तो वहां ना तो पौधे मिले ना ही पेड़। वहां सिर्फ पेड़ों के रूप में लकड़िया ही लगी हुई थी। वह भी पूरी तरह से सुख चुकी थी। क्यों कि पौधे रोपे जाने के बाद वहां ना कोई प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने उस जगह का दोबारा निरिक्षण किया न ही किसी जनप्रतिनिधि ने। जिसके चलते पौधे लकड़ियों के रूप तब्दील होकर सुख चुके थे। इस मामले में जब नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र कुमार दीक्षित से बात की तो उनका कहना था कि पानी की समस्या के चलते पेड़ सुख गए है। नगर पालिका ने उस जगह को अमृत-2 ट्री योजना में लिया है। जिसके चलते समूह की महिलाओं के द्वारा पौधे का रखरखाव किया जाएगा।

तकनीक का मानवीय चेहरा

नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 ने एक बार फिर यह सवाल केंद्र में ला दिया कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज विकास का सबसे चर्चित औजार बन चुका है, लेकिन उसके साथ जुड़ी चिंताएं भी कम नहीं हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि एआई तभी सार्थक है, जब उसमें विवेक, तर्क और सही निर्णय लेने की क्षमता हो, एक दूरदर्शी सोच को दशार्ता है। तकनीक का उद्देश्य केवल सुविधाएं बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज की जमीनी समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है, जब इसका लाभ शहरों और बड़े संस्थानों तक सीमित न रहकर गांवों, कस्बों और हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंचे। वरना तकनीक विकास का नहीं, बल्कि असमानता का औजार बनकर रह जाएगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में दिखाई दी नवाचार की झलक इस बात का प्रमाण है कि देश की युवा प्रतिभा बड़े समाधान गढ़ने की क्षमता रखती है। स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और इनोवेटर्स द्वारा प्रस्तुत प्रयोग यह संकेत देते हैं कि भारत केवल तकनीक अपनाने वाला नहीं, बल्कि दिशा देने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। यह आत्मनिर्भरता की उस अवधारणा को भी मजबूत करता है, जिसमें ज्ञान, शोध और नवाचार को विकास की बुनियाद माना गया है। समिट के दूसरे दिन होने वाली पैनल चचार्एं और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों पर आधारित विशेष पुस्तिकाओं का विमोचन इस बात को रेखांकित करता है कि सरकार अब एआई को नीतिगत स्तर पर गंभीरता से लागू करने के मूड में है। एप्लाइड एआई पर केंद्रित सेमिनार यह दशार्ता है कि अब बहस से आगे बढ़कर क्रियान्वयन का समय है। पर यहां सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि तकनीक की रफ्तार के साथ नैतिकता और जवाबदेही भी बनी रहे। जरूरत इस बात की है कि एआई के उपयोग में पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तकनीक अगर रोजगार छीनने का माध्यम बनी, तो सामाजिक असंतोष बढ़ेगा; लेकिन अगर वही तकनीक नए अवसर पैदा करे, तो समावेशी विकास का मार्ग खुलेगा। इसलिए नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और समाज-तीनों को मिलकर संतुलन साधना होगा। कुल मिलाकर, एआई समिट 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत तकनीकी प्रगति को मानवीय सरोकारों से जोड़ने के पक्ष में है।

मानव सभ्यता के इतिहास पर दस्तक देती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत में हो रही समिट

बिनोद लाकियावाला
स्तंभकार

नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच आयोजित 'एआई इम्पैक्ट 2026' केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं,बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में एक नए अध्याय का उद्घोष है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया, तो यह केवल दीप प्रज्ज्वलन नहीं था, बल्कि उस भविष्य का उद्घाटन था जिसमें मशीनें केवल उपकरण नहीं, बल्कि मानव निर्णय,शासन, अर्थव्यवस्था और चेतना की संरचना में सहभागी होंगी। .भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह आयोजन एक प्रयोगशाला नहीं,बल्कि एक प्रयोग-भूमि है, जहाँ करोड़ों जीवन की दिशा तय होनी है।

हर तकनीकी क्रांति के साथ आशंकाओं की आँधी भी आती है। औद्योगिक क्रांति ने श्रमिक वर्ग को विस्थापित किया था, सूचना क्रांति ने ज्ञान का केंद्रीकरण तोड़ा था, और अब एआई क्रांति मानव श्रम और मानव निर्णय दोनों को चुनौती दे रही है। भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी पहले से ही सामाजिक- आर्थिक तनाव का स्रोत है,वहाँ एआई का आगमन एक नई अनिश्चितता का संकेत भी है। क्या मशीनें करोड़ों नौकरियों को निगल जाएँगी? क्या मानव श्रम अप्रासंगिक हो जाएगा? क्या निर्णय-प्रक्रिया एल्गोरिद्म के हाथों में चली जाएगी? ये प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दार्शनिक और राजनीतिक भी हैं।एआई इम्पैक्ट 2026 का केंद्रीय विमर्श इसी द्वंद्व पर केंद्रित है–संभावना और शंका, सफलता और संकट,विकास और विस्थापन। प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण इस द्वंद्व को स्वीकारते हुए आशावाद की ओर झुका हुआ था। उन्होंने कहा कि एआई मानव को विस्थापित नहीं, बल्कि सशक्त करेगा।यह कथन राजनीतिक रूप से आश्वस्तकारी है, परंतु सामाजिक यथार्थ में इसे मूर्त रूप देने के लिए नीतिगत क्रांति आवश्यक है।

भारत की विशाल जनसंख्या यदि प्रशिक्षित, कौशलयुक्त और डिजिटल रूप से सशक्त होती है, तो एआई क्रांति भारत को वैश्विक शक्ति बना सकती है। किंतु यदि यह जनसंख्या तकनीकी परिवर्तन से कट जाती है,तो वही जनसंख्या सामाजिक विस्फोट का कारण भी बन सकती है।एआई इम्पैक्ट 2026 इस दोराहे पर खड़े भारत का आत्ममंथन है।मानव संसाधन के संदर्भ में एआई का प्रभाव बहुआयामी है। शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएँ, कृषि, उद्योग, प्रशासन, न्याय प्रणाली–सभी क्षेत्रों में एआई की भूमिका बढ़ रही है।भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, और अब एआई आधारित शासन मॉडल, एक नए सामाजिक अनुबंध की रचना कर रहे हैं।मोदी का मिशन इस अनुबंध को 'डिजिटल नागरिकता' के रूप में परिभाषित करता है। एआई इम्पैक्ट 2026 इसी डिजिटल नागरिकता का वैश्विक विमर्श है।बेरोजगारी की आशंका को लेकर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय विभाजित है। कुछ का मानना है कि एआई करोड़ों नौकरियों को समाप्त कर देगा, जबकि अन्य का कहना है कि यह उतनी ही नई नौकरियाँ भी पैदा करेगा। भारत के संदर्भ में यह समीकरण अधिक जटिल है। यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि आधारित रोजगार और निम्न कौशल श्रमिकों की विशाल संख्या है। यदि एआई इन क्षेत्रों में बिना सामाजिक सुरक्षा के प्रवेश करता है, तो असमानता बढ़ेगी। एआई इम्पैक्ट 2026 में इस प्रश्न पर गहन चर्चा हो रही है कि कैसे कौशल पुनर्संरचना, जीवनपर्यंत शिक्षा और डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन को एआई युग के अनुरूप ढाला जाए।

मोदी ने 'एआई फॉर ऑल' की अवधारणा पर जोर देकर इस समावेशन का संकेत दिया। उनका कहना था कि एआई केवल महानगरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति नहीं, बल्कि गाँव, किसान, छात्र और छोटे उद्यमी का भी अधिकार है। एआई इम्पैक्ट 2026 में प्रस्तुत अनेक स्टार्टअप और नीति प्रस्ताव इसी विचार को मूर्त रूप देते हैं।वैश्विक मंच पर भारत की एआई कूटनीति भी इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण आयाम है। एआई अब ऊर्जा, रक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक प्रभुत्व का नया क्षेत्र बन चुका है। अमेरिका और चीन के बीच एआई प्रतिस्पर्धा एक नई शीत युद्ध की तरह उभर रही है। भारत इस प्रतिस्पर्धा में तीसरे ध्रुव के रूप में उभर सकता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों पर आधारित एआई मॉडल प्रस्तुत करे। प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन वक्तव्य इसी 'विश्व मित्र' भूमिका की ओर संकेत करता है। एआई इम्पैक्ट 2026 में यह भी स्पष्ट हुआ कि डेटा ही नए युग का तेल नहीं, बल्कि नई सभ्यता का रक्त है। भारत के पास विशाल डेटा संसाधन हैं, परंतु डेटा संप्रभुता, निजता और सुरक्षा के प्रश्न अत्यंत संवेदनशील हैं। यदि भारतीय नागरिकों का डेटा वैश्विक तकनीकी निगमों के नियंत्रण में चला गया, तो डिजिटल उपनिवेशवाद का खतरा वास्तविक है। इस सम्मेलन में डेटा लोकलाइजेशन, भारतीय एआई मॉडल और स्वदेशी चिप निर्माण पर हुई चर्चा भारत की डिजिटल संप्रभुता के संघर्ष का संकेत है।

बेरोजगारी की आँधी की आशंका इस सम्मेलन के विमर्श में बार-बार उभरी। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि आने वाले वर्षों में पारंपरिक नौकरियाँ तेजी से समाप्त होंगी। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि एआई नई रचनात्मक अर्थव्यवस्था को जन्म देगा, जहाँ मानव रचनात्मकता, भावनात्मक बुद्धि और सामाजिक कौशल की मांग बढ़ेगी। भारत के लिए यह संक्रमण काल सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ सामाजिक सुरक्षा तंत्र अभी भी विकसित हो रहा है। इसलिए एआई नीति के साथ-साथ सामाजिक नीति भी उतनी ही आवश्यक है।

नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 'मानवता प्रथम' का मंत्र दोहराया। यह मंत्र केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि नीति का आधार बन सकता है। यदि भारत एआई को मानव कल्याण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपयोग करता है, तो यह तकनीक सामाजिक समानता का उपकरण बन सकती है। एआई इम्पैक्ट 2026 इसी नैतिक दृष्टि को वैश्विक विमर्श में स्थापित करने का प्रयास है।सफलता की राह स्पष्ट है, परंतु सरल नहीं। भारत को एआई शिक्षा को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में एकीकृत करना होगा।शोध, नवाचार और उद्योग के बीच सेतु बनाना होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रामीण भारत तक विस्तार देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, एआई के नैतिक और कानूनी ढाँचे का निर्माण करना होगा। एआई इम्पैक्ट 2026 इन सभी क्षेत्रों में नीति-निर्माताओं, उद्योग और अकादमिक जगत के बीच संवाद का मंच प्रदान करता है। एआई इम्पैक्ट 2026 इसी तूफान और अवसर के संगम पर खड़ा भारत का आत्म चिंतन है।यह सम्मेलन हमें याद दिलाता है कि तकनीक का भविष्य केवल इंजीनियरों के हाथ में नहीं, बल्कि समाज,नीति, दर्शन और लोकतंत्र के हाथ में है। यदि भारत इस सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है,तो एआई युग में वह केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि दिशा-निर्देशक बन सकता है। प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण इसी दिशा का संकेतक है।एआई इम्पैक्ट 2026 इसलिए एक सम्मेलन नहीं,बल्कि एक चेतावनी, एक संकल्प और एक सभ्यतागत संवाद है।मानव और मशीन के इस नए सहजीवन में भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है -यदि वह अपनी प्राचीन विवेक परंपरा और आधुनिक तकनीक को संतुलित कर सके।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

विकास की धड़कन बना ब्रम्हपुत्र पर सेतु अंडर वाटर टनल से बदलती तस्वीर

कांतिलाल मांडोत
स्तंभकार

असम की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी की जनसभा में भारत माता की जय का उद्घोष किया था , तो वह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि उत्तर-पूर्व के विकास को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश भी था। उनके संबोधन में संगठन की शक्ति, कार्यकर्ताओं के समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की झलक दिखाई दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2014 के बाद उत्तर-पूर्व को प्राथमिकता दी गई है और यह क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम, जो लंबे समय तक भौगोलिक दूरी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पिछड़ा माना जाता था, आज बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए नए युग में प्रवेश कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 6-लेन के आधुनिक पुल कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है, जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बन जाने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर मात्र सात मिनट रह जाएगा। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ब्रह्मपुत्र, जो असम की जीवनरेखा है, अब विकास का सेतु बन चुकी है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि पिछले वर्षों में उत्तर-पूर्व के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र की प्रतिभा और सांस्कृतिक समृद्धि को राष्ट्रीय मंच पर उचित पहचान मिल रही है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस भूभाग को अब देश के विकास मानचित्र में प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। विकास की इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर रेल एवं सड़क टनल को मंजूरी दी है। यह परियोजना गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच बनाई जाएगी। लगभग 15.8 किलोमीटर लंबी यह टनल तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल और महत्वाकांक्षी है। पूरे प्रोजेक्ट, जिसमें अप्रोच रोड और रेलवे ट्रैक भी शामिल हैं, की लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 18,600 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस टनल के बन जाने से वर्तमान में 240 किलोमीटर की दूरी घटकर लगभग 34 किलोमीटर रह जाएगी। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क भी सुदृढ़ होगा। यह परियोजना सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपात स्थिति में सेना और आवश्यक संसाधनों की तेजी से आवाजाही संभव हो सकेगी। एक ट्यूब में सिंगल रेल ट्रैक की सुविधा होगी और ट्रेनें बिजली से संचालित होंगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि ट्रेन के गुजरने के दौरान सड़क यातायात नियंत्रित रहेगा। इसमें बैलिस्टिक ट्रैक जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसे अत्याधुनिक संरचना बनाता है।

इन परियोजनाओं का महत्व केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है। उत्तर-पूर्व भारत लंबे समय से भौगोलिक अलगाव और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण आर्थिक रूप से पीछे रहा है। जब मजबूत पुल, आधुनिक सड़कें और सुरक्षित रेल नेटवर्क तैयार होते हैं, तो वे केवल दो स्थानों को नहीं जोड़ते, बल्कि संभावनाओं को जोड़ते हैं। इससे उद्योग, कृषि, पर्यटन और छोटे व्यवसायों को नई ऊर्जा मिलती है। असम, जो प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध है, अब बेहतर संपर्क के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में संगठन की शक्ति और कार्यकर्ताओं के योगदान का विशेष उल्लेख किया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी पहुंची है, वह कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रजीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति होती है। यह संदेश केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरक है। उत्तर-पूर्व के विकास की यह नई कहानी केवल सरकारी योजनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि विश्वास, संकल्प और क्रियान्वयन का उदाहरण है। असम में बन रहे ये बड़े प्रोजेक्ट इस बात के संकेत हैं कि अब यह क्षेत्र देश के विकास की परिधि में नहीं, बल्कि केंद्र में है। पुल और टनल जैसी संरचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेंगी।

गुवाहाटी की सभा में गूंजा 'भारत माता की जय' का उद्घोष केवल एक नारा नहीं, बल्कि उस भावना का प्रतीक है जो विकास, एकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को आगे बढ़ा रही है। असम और पूरा उत्तर-पूर्व अब उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जो बुनियादी ढांचे से लेकर राष्ट्रीय पहचान तक हर स्तर पर दिखाई दे रहा है। यह समय है जब ब्रह्मपुत्र की धारा के साथ विकास की धारा भी समानांतर बह रही है, और उत्तर-पूर्व भारत के उज्ज्वल भविष्य की नई इबारत लिखी जा रही है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

रिसर्च

बिच्छुओं को पसंद है खास मिट्टी, डंक मारने वाले इन शिकारियों की मैपिंग शुरू

दुनियाभर में हर साल 10 से 20 लाख लोग बिच्छू के डंक का शिकार होते हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में सिर्फ दर्द और सूजन ही होती है, लेकिन कई बार यह जानलेवा साबित होता है। एक चौंकाने वाले आंकड़े के मुताबिक, जहरीले बिच्छुओं के कारण हर साल लगभग 3,000 बच्चों की मौत हो जाती है। मोरक्को जैसे शहरी इलाकों से लेकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक, बिच्छू मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में पता लगाया है कि ये खतरनाक शिकारी जीव अपनी रहने की जगह चुनने के मामले में बहुत 'चूजी' होते हैं और उन्हें खास तरह की मिट्टी ही पसंद आती है।

यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे की वेनम सिस्टम्स लैब के प्रमुख मिशेल डुगन और उनकी अंतरराष्ट्रीय टीम की स्टडी 'एनवायरमेंटल रिसर्च कम्युनिकेशंस' जर्नल में छपी है। इस स्टडी में मोरक्को को आधार बनाकर बिच्छुओं के रहने के ठिकानों की मैपिंग की गई है। रिसर्चर्स ने पाया कि तापमान या मौसम से ज्यादा, मिट्टी का प्रकार यह तय करता है कि किस इलाके में सबसे जहरीले बिच्छू पनपेंगे। यह जानकारी भविष्य में बिच्छू के डंक से होने वाली मौतों को रोकने में गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

बिच्छुओं का मिटटी से लगाव: वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडलिंग और सालों के फील्ड ऑब्जर्वेशन को मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला है। इनकी 2,000 से ज्यादा प्रजातियों में से केवल 100 ही जानलेवा हैं। ये जहरीली प्रजातियां हर तरह की जमीन पर नहीं रहतीं। वे मिट्टी की बनावट, उसकी नमी सोखने की क्षमता और खुदाई की सुगमता के आधार पर अपना घर चुनते है। रिसर्च बताती है कि अगर स्वास्थ्य विभाग को यह पता हो कि किस तरह की मिट्टी में ये बिच्छू फल-फूल रहे हैं, तो उन खास इलाकों में पहले से ही बचाव के इंतजाम किए जा सकते हैं।

बच्चों को बचाने में मिलेगी मदद: मिशेल डुगन के अनुसार, बिच्छू के डंक का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है क्योंकि उनका शरीर जहर के मुकाबले छोटा होता है। इस नई मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य अधिकारी उन हाई-रिस्क इलाकों की पहचान कर सकते हैं जहां जहरीले बिच्छुओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। वहां के अस्पतालों में एंटी-वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है और स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा सकता है। यह तकनीक न केवल मोरक्को बल्कि ब्राजील, मिडिल ईस्ट और भारत जैसे देशों में भी जीवन बचाने के लिए लागू की जा सकती है।

अब तक वैज्ञानिकों का ध्यान ज्यादातर जहर के इलाज पर था, लेकिन यह स्टडी उनकी इकोलॉजी यानी रहने के ढंग को समझने पर जोर देती है। डॉक्टर फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ को बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बिच्छुओं के ठिकानों की सटीक जानकारी होने से भविष्य में जहरीले एनकाउंटर्स को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

सुविचार

शांति की इच्छा हो तो
पहले इच्छा को शांत करो।
-अज्ञात

निशाना

पत्थरों के शहर में...!

कुमार अखिलेश

अपनी संस्कृति की जड़ों से कटते जा रहें हैं,
पश्चिमी सभ्यता की होड़ में मिटते जा रहें हैं।
कद तो हमारा बढ़ रहा है, तरक्की के दौर में,
मगर खुद के अंदर ही, सिमटते जा रहे हैं।
अपना नाम दुनिया में बढ़ाने के लिए,
हम धीरे धीरे खुद में, घटते जा रहें है।
अपनी एक अलग दुनिया बनाने के लिए,
आपस में हम सभी, बटते जा रहें है।
आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम सभी,
अपने निर्धारित लक्ष्यों से, हटते जा रहें है।
नुमाइश की इस दुनिया में आज हम सभी,
इसके मायाजाल में, फंसते जा रहें है।
दुनिया आज खड़ी है, बारूद के दल दल पर,
धीरे धीरे सभी इसमें, धंसते जा रहे।
गाँवों की मिट्टी की खुशबू छोड़कर लोग,
पत्थरों के शहर में, बसते जा रहें है।

यूजर्स गाइड

सीजन में पहली बार AC चलाएं तो कुछ सावधानियों से सुरक्षित रहेगी मशीन

इस बार मौसम ने बहुत जल्द तेवर तीखे कर लिए हैं। आधा फरवरी खत्म ही हुआ है कि दोपहर गर्म महसूस होने लगी है। ऐसा ही चलता रहा, तो कुछ ही दिनों में लोगों को एयर कंडीशनर शुरू करने पड़ेंगे। आप भी ऐसा करें, तो ध्यान रखें कि सीजन की शुरुआत में पहली बार AC ऑन करते समय कुछ काम जरूर कर लेने चाहिए।

ऐसा न करने पर स्विच ऑन करते ही एयर कंडीशनर में कोई खराबी आ सकती है और कोई न कोई बड़ा खर्चा आपके गले पड़ सकता है। पहली बार AC शुरू करने से पहले उसकी हार्ड या सॉफ्ट सर्विस, कंडेंसर और आउटडोर यूनिट की जांच, ड्रेन पाइप और लीकेज की जांच, वोल्टेज और स्टेबलाइजर सेटअप करना और सही मोड का ध्यान रखना जरूरी होता है।

AC को गर्मियों में पहली बार शुरू करने से पहले सर्विस जरूर करवा लें। किसी वजह से अगर हार्ड सर्विस में देरी हो रही हो तो खुद सॉफ्ट सर्विस कर लें। बता दें कि हार्ड सर्विस टेक्नीशियन जरूरी टूल्स के साथ करते हैं। वहीं सॉफ्ट सर्विस में आप फिल्टर की सफाई, एक खराब टूथब्रश और पानी से कॉइल की सफाई और संभव हो, तो तेज पानी की धार से विडों AC की पीछे से और स्प्लिट एसी के आउटडोर युनिट की सफाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में स्प्लिट एयर कंडीशनर है, तो उसके कंडेंसर और आउटडोर यूनिट को चेक कर लें। कंडेंसर आउटडोर यूनिट के पीछे मौजूद जाली को कहते हैं, तो कि लंबे समय से बंद पड़े-पड़े धूल-मिट्टी से ब्लॉक हो जाती है। उसे तेज पानी की धार से धो लें। इसके अलावा देखें कि आउटडोर यूनिट सामने या आसपास कम से कम 2-3 फीट तक कोई रुकावट न हो। AC स्विच ऑन करने के बाद गौर करें कि आउटडोर फैन या कंप्रेसर से तेज खड़कड़ाहट की आवाज तो नहीं आ रही है?

ड्रेन पाइप और लीकेज की जांच: लंबे समय से AC बंद होता है, तो उसमें गंदगी इकट्ठा होने के चलते लीकेज की समस्या आ सकती है। ऐसे में स्प्लिट ष्ट को पहली बार ऑन करने से पहले उसके ड्रेन पाइप को चेक कर लें। AC को ऑन करने से पहले चेक करें कि स्टेबलाइजर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा AC के प्लग को भी चेक करें कि कहीं भी तार कटी न हो और न ही AC का प्लग ढीला हो। अगर आप स्टेबलाइजर से जुड़ी AC की तारों को खोलकर उन्हें नए सिरे से कस दें, तो स्टेबलाइजर से जुड़ी कोई समस्या आने की गुंजाइश कम हो जाती है। AC को पहली बार शुरू करते समय उसे फैन मोड पर शुरू करें। ऐसे में हो सकता है कि AC के अंदर से कुछ गंदगी बारह आए (अगर AC हार्ड सर्वस नहीं हुआ है, तो) साथ ही अगर AC में किसी तरह की समस्या होगी, तो वह भी फैन मोड पर बिना कंप्रेसर के ऑन हुए पता चल जाएगी। जिससे कंप्रेसर तक खराबी नहीं पहुंच पाती।

अजब - गजब

समुद्र से निकला पुराना खजाना, अलेक्जेंड्रिया लाइटहाउस के पत्थर खोलेंगे इतिहास का राज

समुद्र की लहरों के नीचे पिछले कई सदियों से दबे पड़े इतिहास को फिर से उजागर करने का काम शुरू हो गया है। अलेक्जेंड्रिया के तट के पास गोताखोरों और भारी क्रेनों की मदद से प्राचीन अलेक्जेंड्रिया के विशाल पत्थरों को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाला जा रहा है। इस संरचना को Pharos of Alexandria के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दौर में शहर के बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। इसकी गिनती प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में की जाती है। साल 1995 में पानी के भीतर इसके अवशेषों की पहचान होने के लगभग 30 साल बाद अब रिसर्चर्स चुनिंदा आर्किटेक्चरल टुकड़ों की डिटेल स्टडी के लिए बाहर निकाल रहे हैं। यह काम फ्रांस के नेतृत्व वाले 'PHAROS प्रोजेक्ट' का हिस्सा है, जिसका मकसद बरामद पत्थरों और भूमध्यसागर के नीचे मैप किए गए टुकड़ों के आधार पर लाइटहाउस का डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन करना है।

अब तक 22 बड़े पत्थर समुद्र से निकाले जा चुके हैं। इनमें से कुछ का वजन 70 से 80 टन के बीच है। बरामद टुकड़ों में विशाल दरवाजों के ऊपरी चौखट, साइड फ्रेम, दहलीज और बड़े आधार पत्थर शामिल हैं। इन खास खोजों में हेलेनिस्टिक काल की मिस्त्री शैली का एक अज्ञात पायलन (प्रवेश द्वार संरचना) भी मिला है। इन पत्थरों का आकार लाइटहाउस की मूल भव्यता और विशालता का अंदाज़ा देता है। हर ब्लॉक को जमीन पर लाकर डिटेल स्टडी के बाद आगे की वैज्ञानिक जांच की जा रही है। डिजिटल तकनीक से वर्चुअल पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की जाएगी। बरामद पत्थरों को फोटोग्रामेट्री तकनीक से स्कैन किया जाएगा। ये टुकड़े पिछले एक दशक में पानी के भीतर डिजिटाइज़ किए गए 100 से अधिक ब्लॉकों के साथ जोड़े जाएंगे।

इंजीनियर डेटा का विश्लेषण कर प्रत्येक पत्थर को वर्चुअल वातावरण में उसकी संभावित मूल स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। इसका उद्देश्य यह समझना है कि लाइटहाउस का निर्माण कैसे हुआ और अंततः यह कैसे ध्वस्त हो गया। सिमुलेशन की मदद से संरचना का एक 'Digital Twin' तैयार किया जाएगा, जिससे लोग बिना वास्तविक पुनर्निर्माण के ही प्राचीन फरोस को विस्तार से देख सकेंगे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में Ptolem4 प्रथम के शासनकाल में निर्मित यह लाइटहाउस लगभग 100 मीटर ऊंचा माना जाता है। यह खतरनाक मानी जाने वाली समुद्री तटरेखा पर जहाजों का गाइडेंस करता था और भूमध्यसागर के रूट पर व्यापार में अलेक्जेंड्रिया की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था।

न्यूज विंडो

नपाध्यक्ष ने राजघाट निर्माण का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया जोर

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम् का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राजघाट का जीर्णोद्धार कार्य का मंगलवार को नपाध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नपाध्यक्ष ने चल रहे कार्य की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए और निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन हो। इस दौरान उपयंत्री आयुषी रिछारिया और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि अजय नागेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।उपयंत्री आयुषी रिछारिया ने बताया कि राजघाट जीर्णोद्धार का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रिटर्निंग वॉल का कार्य लगभग 20 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अधिकांश कार्य बारिश शुरू होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। शनिवार को भी नपाध्यक्ष श्रीमती यादव ने कार्य स्थल का निरीक्षण किया था।

बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र में सरकारी स्कूल के शिक्षक छात्रा के साथ किया रेप

बालाघाट। प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र में सरकारी स्कूल के शिक्षक की गंदी करतूत आई सामने। छात्रा को परीक्षा में पास कराने की बात कहकर रेप किया, जब वे विरोध करने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद से आरोपित शिक्षक फरार है। इधर, घटना सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपित शिक्षक को जिला मुख्यालय कार्यालय में अटैच करने के आदेश जारी किए है, लेकिन शिक्षक ने डीईओ कार्यालय में भी अपनी उपस्थित दर्ज नहीं कराई है।

एसपी की जनसुनवाई में आए 26 आवेदन, निराकरण के दिए निर्देश

नर्मदापुरम। जिले के पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा (भापुसे) ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की।जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की 26 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, मारपीट और महिला संबंधी मामले प्रमुख थे। पुलिस अधीक्षक ने हर शिकायत को गंभीरता से सुनकर संबंधित थाना प्रभारियों और अनुभागीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।यह आयोजन आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनसुनवाई का मुख्य लक्ष्य पुलिस-जन संवाद मजबूत करना, न्याय दिलाना और पुलिस प्रशासन में विश्वास बनाए रखना है। यह कार्यक्रम हर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय नर्मदापुरम में नियमित रूप से होता है।

हिंदू लड़की के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक मिले आपत्तिजनक वीडियो; लोगों ने पीटा

खजुराहो। प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में एक होटल में मुस्लिम युवक को हिंदू नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने जब कमरे की तलाशी ली तो नाबालिग अलमारी के अंदर मिली। उसने बाहर निकालकर बचाने की बात कही। रेस्टोरेंट संचालन करने वाले मुस्लिम युवक को स्थानीय लोगों ने और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम लड़के को पहले पीटा। फिर उसको पकड़ कर खजुराहो थाने ले गए। जिसके बाद पुलिस ने लड़की को छतरपुर के महिला थाने आगे के कार्रवाई के लिए भेज दिया है और लड़का वही खजुराहो थाने में है। स्थानीय शिवांक अवस्थी ने बताया कि मुहमद शकील खजुराहो में किराए से रेस्टोरेंट संचालित करता है, और वह हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है,अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर, आरोपी के फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। हालांकि, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एक युवक-युवती के साथ किसी अपना रेस्टोरेंट के कमरा नंबर 103 में मौजूद है। जब सूचना मिली तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। इसी बीच शकील ने लड़की को अलमारी में छिपा दिया।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या का आरोप

बीना। नानक वार्ड निवासी एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिसमें परिजनों ने महिला के जेठ व जेठानी पर हत्या करने के आरोप लगाए है। जानकारी के अनुसार मंजू पति दिनेश घोषी (38) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना सुबह करीब 7.30 बजे पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतिका के भाई ब्रजेन्द्र घोषी ने बताया कि उन्हें सुबह 6 बजे घटना की जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का छोटा बेटा आयुष (11) सुबह करीब 5 बजे जागा तो कमरे में मां नहीं मिली। तलाश करते हुए जब वह छत पर पहुंचा तो मां अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली। उसने तुरंत पिता को बुलाया, जिसके बाद महिला को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि मंजू के जेठ सुनील और जेठानी बबीता पिछले करीब पांच वर्षों से जमीन और मकान को लेकर विवाद करते रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों अक्सर जान से मारने की धमकी देते थे। परिजनों का आरोप है कि महिला को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई।

पानी की किल्लत: वार्ड 7 की महिलाओं ने नपा कार्यालय के समक्ष किया विरोध-प्रदर्शन

मंडीदीप में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के वार्ड में नियमित पानी सप्लाई, बाकी 24 वार्ड हैं भगवान भरोसे

अजय आहूजा। मंडीदीप

क्षेत्र में गर्मी की शुरुआत के साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष के वार्ड और उपाध्यक्ष के वार्ड को छोड़कर बाकी सभी 24 वार्डों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप्प-सी हो गई है। कई वार्डों में 4-5 दिन तो कुछ में एक सप्ताह तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे स्थानीय निवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि नपा अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल के वार्ड 05 और उपाध्यक्ष पुष्पा प्रेमशंकर साहू के वार्ड 01 में नियमित रूप से दो दिन छोड़कर पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ठीक अध्यक्ष के वार्ड से सटे वार्ड 07 में 7-8 दिन में भी पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को वार्ड 07 की महिलाओं ने पहले अपने वार्ड में विरोध जताया, फिर नपा कार्यालय पहुंचकर खाली बाल्टी-कुप्पे लहराते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले वार्ड 24 तथा वार्ड 14-16 के निवासियों ने भी पानी की किल्लत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। नपा के दावे के मुताबिक सभी 26 वार्डों में हर दो दिन छोड़कर पानी सप्लाई होना चाहिए, लेकिन पिछले एक सप्ताह से व्यवस्था चरमरा गई है। क्षेत्र के मुख्य जल स्रोत 125 ट्यूबवेल हैं, साथ ही एमपीआईडीसी से रोजाना 1.5 लाख लीटर पानी लिया जाता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, गहराते जलस्तर के कारण एक दर्जन से अधिक ट्यूबवेल पूरी तरह बंद हो गए हैं, जबकि कई अन्य पहले से कम पानी दे रहे हैं। इससे सप्लाई प्रभावित हुई है।

> नपा द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वार्ड को छोड़कर पूरे नगर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है।
> -**गोविन्द राजपूत**, रहवासी मंडीदीप।
>
> मेरे द्वारा वार्ड में हो रहे जल संकट की समस्या उसके समाधान के लिए नपा अध्यक्ष को पत्र दे चुका हूं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है।
> -**दौलतराम उइके**, वार्ड पार्षद 07
>
> पेयजल शाखा के लिए नई मोटर ओर पंप ख़रीदे जा रहे हैं, तीन दिन में व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होने लगेगी।
> -**प्रशांत जैन**, सीएमओ मंडीदीप।

जल संकट से निपटने नपा के पास नहीं कोई ठोस प्लान

क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या और विकराल हो रही है, लेकिन नपा के पास ट्यूबवेल खनन के अलावा कोई दूसरी ठोस योजना नहीं है। रहवासियों का कहना है कि फरवरी माह में पानी की यह स्थिति है तो अप्रैल- मई में क्या हालत होगी। जब पेयजल शाखा से पानी की किल्लत पर बात की तो उन्होंने कहा जहां परेशानी है वहां नये ट्यूबवेल खनन कराये जा रहे है। नपा द्वारा अभी तक सतलापुर में 4 ओर राहुल नगर में एक बोर लगाया जा चुका है।

एक दशक में 3 योजनाएं, धरातल पर एक भी नहीं

प्रदेश सरकार एवं केंद्र द्वारा नपा क्षेत्र के लिए एक दशक में तीन पेयजल योजना बनाई गई, लेकिन जमीन पर अब एक भी नहीं उतर सकी है। पहली योजना के तहत नर्मदा जल के लिए थाने के पास वाल्व छोड़ा गया, लेकिन अमल नहीं हुआ। इसके बाद 15.80 करोड़ से मुख्यमंत्री पेयजल योजना पर काम शुरू किया गया, लेकिन अधूरे निर्माण के साथ योजना को ख़त्म कर दिया गया। वर्तमान में 64 करोड़ रु की अमृत -2 योजना के तहत दाहोद जलाशय से पानी लाने की योजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन योजना कब पूरी होगी किसी को नहीं पता।

अधिकारी का आरोप- ताला बदलकर वेयर हॉउस संचालक ने हेराफेरी की

माखननगर के चीलाचोन एकलव्य वेयर हाउस से 4 करोड़ की मूंग गायब, कॉर्पोरेशन ने दिया पुलिस को आवेदन

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

माखननगर क्षेत्र के ग्राम चीलाचोन स्थित निजी एकलव्य वेयरहाउस से करीब 4 करोड़ रुपये कीमत की मूंग गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने मंगलवार शाम माखननगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिये आवेदन दिया हैं।कॉर्पोरेशन के अनुसार, वर्ष 2023 में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई लगभग 64 हजार बोरियों मूंग का भंडारण एकलव्य वेयर हाउस में किया गया था। स्टॉक भरने के बाद गोदाम को बंद कर ताला लगा दिया गया था।

कर्मचारियों ने स्टॉक का जायजा लिया तो बोरियों में कमी का संदेह हुआ। जानकारी मिलने पर शाखा प्रबंधक हेमंत चंदेल ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया और वेयर हाउस संचालक को बुलाया, लेकिन वह नहीं पहुंचा। टीम ने ताला तोड़कर भंडारित मूँग का सत्यापन किया। निरीक्षण में गोदाम के अंदर लगी

छल्लियो के बीच से 10,500 बोरियां (करीब 4 करोड़ रुपये कीमत) गायब पाई गईं। कॉर्पोरेशन स्टॉक का मिलान कर रहा है।प्रबंधक वासुदेव दावंडे ने बताया, हमने मूंग भंडारण के बाद ताला लगाया था, लेकिन गोदाम के बड़े शटर पर उसी कंपनी का दूसरा ताला लगा मिला हैं। ताला बदलकर ही हेराफेरी की गई।मामले में एफआईआर कराने थाने में आवेदन दिया हैं उधर एक लव्य वेयर हॉउस संचालक आरती नरेंद्र तोमर ने भी माखन नगर थाने में आवेदन देकर कॉर्पोरेशन के अधिकारियो पर साजिश करने का आरोप लगाया हैं साथ तीन साल से वेयर हॉउस का लगभग 85लाख रूपये किराया भुगतान नही होने कि बात भी कही हैं। सोहागपुर एसडीओपी संजू चौहान ने बताया कि ग्राम चीलाचोन वेयरहाउस में मूंग की गड़बड़ी को लेकर वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने आवेदन दिया है। इसकी जांच कर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

पीके कापसे नर्मदापुरम के नए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

नर्मदापुरम। परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के तबादले हुए। नर्मदापुरम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कि कमान पीके कापसे को दी गईं हैं उन्होंने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया हैं अभी तक रिंकू शर्मा नर्मदापुरम कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कि जिम्मेदारी संभाल रही थी उनका तबादला जबलपुर संभागीय मुख्यालय हो गया हैं उन्हें जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की जिम्मेदारी मिली है। जानकारी के अनुसार पीके कापसे ने नर्मदापुरम परिवहन कार्यालय में दूसरी बार ज्वाइन किया है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में भी उनका तबादला नर्मदापुरम क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए हुआ था। तब तबादले आदेश के चलते क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने स्टे ले आई थी। जिसके चलते पीके कापसे को चार्ज वापस देना पड़ा था। स्टे के बाद निशा चौहान डेढ़ साल से ज्यादा नर्मदापुरम में रही। उनके तबादले के बाद जून 2025 में रिंकू शर्मा ने ज्वाइन किया। रिंकू शर्मा का कार्यकाल नर्मदापुरम में आठ माह का रहा हैं

युवक के साथ भागी महिला, पति ने बच्चों को बेचने का संदेह जताया

सिरोंज। दोपहर मेट्रो

क्षेत्र के ग्राम इकलोद में रहने वाली दो बच्चों की मां गांव में ही रहने वाले युवक के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। महिला के पति ने पथरिया थाने में आवेदन देकर अपनी पीढ़ा व्यक्त की है। जिसमें उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर में उनकी पत्नी घर से भाग गई है। वह साथ में 3 और 4 साल के दो बेटों को भी ले गई है। इसके साथ ही वह घर में रखी 1 सोने की चेन, 1 चांदी की करधोनी, 2 चांदी के कड़े, चांदी की पायल और 20 हजार रूपए नगद लेकर गई है। आवेदन में महिला के पति ने बताया कि वह गांव में ही रहने वाले युवक के साथ उसकी बाइक से गई है और भोपाल रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। युवक ने अपने दोनों बच्चों को बेचे जाने और मारे जाने का संदेह भी आवेदन में व्यक्त किया गया। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी रितुराज सिंह ने बताया कि मामले में गुमशुदी का प्रकरण दर्ज किया गया है। हम महिला की तलाश कर रहे हैं।

वार्षिक उत्सव पर दी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बांटे पुरस्कार

सिरोंज। दोपहर मेट्रो

नगर के शासकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय का वर्ष 2025-26 का वार्षिक स्नेह सम्मेलन रंगारंग कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवकुमार भार्गव द्वारा मॉ सरस्वती एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ प्रारम्भ हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लालचंद राजपूत ने प्रारम्भ में महाविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा महाविद्यालय के विकास में किए गए योगदान को याद किया। क्षेत्रीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा के प्रयासों से महाविद्यालय में

चल रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय के प्रारंभ से ही चल रही सबसे बड़ी समस्या महाविद्यालय के ग्राउंड से निकली हाई टेंशन लाइन का शिफ्टिंग का कार्य किस प्रकार से माननीय विधायक जी के प्रयास से संभव हो पाया। खेल गतिविधियों का प्रतिवेदन महाविद्यालय के कीड़ा अधिकारी डॉक्टर वसीम उल्ला खान ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता चंडीगढ़ में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले महाविद्यालय के छात्र बंटी गुर्जर, नरेश अहिरवार एवं काजल सोनी को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तीन दिवसीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत महाविद्यालय में भाषण, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली, केश-सज्जा, सलाद-सज्जा, क्ले मॉडलिंग, नाटक, फैंसी ड्रेस, एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य एवं समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

मेट्रो एंकर | श्री शांतिनाथ जिनालय के स्थापना महोत्सव पर हुआ आयोजन

नगर में निकला चल समारोह, रंगोली से सजीं गलियां, थिरके युवा

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

त्योंदा रोड स्थित श्री शांतिनाथ जैन मंदिर के 18वें स्थापना महोत्सव के पावन अवसर पर नगर जिनभक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर हो उठा। प्रभु भक्ति के दिव्य वातावरण में विमान जी चल समारोह का भव्य आयोजन किया गया जिसने नगर को धर्ममय बना दिया। चल समारोह शांतिनगर त्योंदा रोड से प्रारंभ होकर त्योंदा रोड, महावीर मार्ग होते हुए पुरानी गल्ला मंडी स्थित पावन पंचकल्याणक स्थल अयोध्या नगरी तक पहुंचा। दिव्य घोष, मंगल गान और जय-जिनेंद्र के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। महिला मंडल एवं बालिका मंडल की भक्तिमय प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं के हृदय को भावविभोर कर दिया। चांदी की पालकी में विराजमान भगवान शांतिनाथ स्वामी की अनुपम छवि चल समारोह की शोभा को चार चांद लगा रही थी। मार्ग में श्रद्धालुओं ने अपने-अपने घरों के बाहर सुंदर रंगोलियां सजाईं, दीप प्रज्वलित किए और जिनबिंब की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। चल समारोह का समापन कार्यक्रम स्थल अयोध्या नगरी में हुआ।

नगर परिषद से रैली निकालकर थाने पहुंचे कर्मचारी, अध्यक्ष प्रतिनिधि पर कार्रवाई की मांग

धामनोद में जातिसूचक टिप्पणी का आरोप, सफाईकर्मियों का सामूहिक अवकाश

धार। दोपहर मेट्रो

धामनोद नगर परिषद की स्वच्छता शाखा के कर्मचारी मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार पर सफाई संरक्षक मनोज मेवाती के साथ कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धामनोद थाने पर प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों के अनुसार घटना को लेकर 21 जनवरी को धामनोद थाने में एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था। उनका आरोप है कि एक माह बीत जाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी। गत दिवस कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर नगर परिषद कार्यालय से तख्तियां लेकर रैली निकाली और थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

आश्वासन: मामले की जांच कर करेंगे कार्रवाई

धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सफाई संरक्षक मनोज मेवाती ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वे न्याय मिलने तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना भी पूर्व में संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी। धामनोद नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी पत्र जारी कर उच्च अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।

न्यूज विंडो

कर्मचारियों का 3 माह से वेतन लंबित होने से आर्थिक संकट गहराया

तेंदूखेड़ा। जनपद पंचायत में पदस्थ कर्मचारियो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष बागरी को एक ज्ञापन सोपा है जिसमें उल्लेख किया है विगत एक वर्ष से वेतन के अनियमित भुगतान एवं पिछले तीन माह दिसम्बर 2025, जनवरी 2026 एवं फरवरी 2026 के पूर्णत- लंबित वेतन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। कर्मचारियों के अनुसार बजट आवंटन के अभाव में नियमित वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें एवं उनके आश्रित परिवारों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे निरंतर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु वेतन न मिलने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। समस्त कर्मचारियों ने शासन एवं प्रशासन से विनम्र आग्रह किया है कि लंबित तीन माह का वेतन शीघ्र अति शीघ्र जारी किया जाए तथा आगामी माहों में नियमित रूप से बजट आवंटन सुनिश्चित कर समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए। साथ ही, संचालनालय स्तर से समयबद्ध बजट जारी करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी माहों में नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो वे सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

धानमंडी के कपड़ा मार्केट में दबिश देकर 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार

धार। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धानमंडी क्षेत्र के कपड़ा मार्केट में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 5 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से हजारों की नगदी और ताश पत?तों को जप्?त किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा के मार्गदर्शन में जुआ-सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई थी। इस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि धानमंडी कपड़ा मार्केट वाली गली में कुछ लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे ताश के पत्तों से हार-जीत का दांव लगा रहे हैं। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से घेराबंदी की और जुआ खेल रहे पांचों आरोपियों को दबोच लिया। टीम ने मौके से मुदस्सर पिता नजर मंसूरी निवासी पिंजारवाड़ी, मुदस्सर पिता नजर मंसूरी पिंजारवाड़ी, अफजल पिता रशीद खां काजीवाड़ा, शाहनवाज उर्फ सानू पिता गोरे खां उटावद दरवाजा और तफज्जुल पिता मुस्ताक शेख हटवाड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 22 हजार रुपये नगद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक अरविंद चौहान, अजय चौहान, मनीष सोलंकी, आरक्षक रामनरेश यादव और राममूर्ति की भूमिका रही।

गिट्टी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

सागर। जिले में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर शसंदीप जी आर के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सागर तहसील अंतर्गत ग्राम आपचन्द में खनिज विभाग द्वारा गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया गया। जब्त वाहन को थाना सनोधा में खड़ा कराया गया है। खनिज अधिकारी ने बताया कि प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

तारादेही थाना क्षेत्र की घटना: शादी समारोह से लौट रहे थे लोग

पिकअप और आटो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में डेढ़ दर्जन हुए घायल, 6 जबलपुर रेफर

तेन्दूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

गत दिवस शाम करीब 7 बजे थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है। हादसे में तेज रफ्तार दो वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। हादसा तारादेही मार्ग पर हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई है। तारादेही-तेंदूखेड़ा मार्ग पर बहेरिया के पास अंधे मोड़ पर हुए हादसे में में डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए और 6 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है।

जानकारी अनुसार तारादेही थाना क्षेत्र के शिवलाल खमरिया से अहिरवार समाज के लोग पिकअप वाहन से बारात लेकर पंडा बाबा आए थे, जहां से वापस शिवलाल खमरिया जा रहे थे। अधें मोड़ पर अचानक तारादेही की ओर से आ रहे आटो वाहन से भिड़ंत हो गई, दोनों वाहन तेज रफ्तार में होने के कारण पलट गए। हादसे में घायलों को दूसरे पिकअप वाहन से स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसमें रीना पिता मुकेश अहिरवार उम्र 13 वर्ष निवासी पौड़ी थाना पाटन जिला जबलपुर, बारेलाल पिता दौलत अहिरवार 51 शिवलाल खमरिया थाना तारादेही, चंदन पिता हरिदास अहिरवार उम्र 12 वर्ष निवासी शिवलाल खमरिया थाना तारादेही, रुपलाल अहिरवार उम्र 59 निवासी शिवलाल खमरिया हरिदास पिता लटोरी अहिरवार उम्र 35 वर्ष

निवासी शिवलाल खमरिया दम्मू पिता चखाई अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी बीना बारह थाना महाराजपुर जिला सागर, कैलाश अहिरवार उम्र 46 कुदपुरा थाना तारादेही, शिवलाल पिता मिठाई लाल अहिरवार उम्र 58 वर्ष पौड़ी थाना तारादेही, लक्ष्मण पिता काल्लू अहिरवार उम्र 55 वर्ष निवासी बैलढाना थाना तेंदूखेड़ा, रतनलाल पिता जीवन अहिरवार उम्र 39 वर्ष निवासी पुरा थाना तेजगढ़ हैं। यह घायल पिकअप वाहन से शिवलाल खमरिया जा रहे थे। साथ ही आटो वाहन में राजकुमार पिता मनोज नुनिया उम्र 25 वर्ष निवासी सहजपुर सीमा पति राजकुमार उम्र 23 वर्ष निवासी सहजपुर चाहत पिता विनेश नुनिया उम्र 14 वर्ष निवासी सहजपुर दिवांशी पिता राजकुमार नुनिया उम्र 5 वर्ष निवासी सहजपुर हैं। चारों तेन्दूखेड़ा थाना क्षेत्र सहजपुर निवासी जो कबाड़ा खरीददारी करने गांव गांव जाते हैं और कबाड़ा खरीदकर वापस अपने आटों से सहजपुर आ रहे थे, लेकिन हादसे में घायल हो गए।

घायलों की गंभीर हालत

इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं जिनमे से 6 लोगों को गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जिसमें राजकुमार नुनिया 25 वर्ष सीमा नुनिया, उम्र 23 वर्ष चाहत नुनिया उम्र 14 वर्ष दिवांशी नुनिया उम्र 5 वर्ष यह सभी आटों वाहन में सवार थे। तेन्दूखेड़ा थाना क्षेत्र सहजपुर निवासी हैं। साथ ही लक्ष्मण अहिरवार 39 वर्ष और शिवलाल अहिरवार 58 वर्ष को रेफर किया गया है ये दोनों पिकअप वाहन में थे इनकी हालत गंभीर होने के चलते जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

जानवर को बचाने में हुआ हादसा

घटना की सूचना मिलते ही तेन्दूखेड़ा थाने से डायल 112 से पायलट संदीप अहिरवार सैनिक 272 पूरन सिंह मौके पर पहुंचे और आटों वाहन वाहन मे फंसे हुए घायलों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र भेजा साथ ही सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रावेन्द्र बागरी अपने स्टाफ के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और हादसे की जानकारी घायलों से ली और मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की गई। बताया गया है यह हादसा मोड़ पर अचानक से जंगली जानवर निकलकर सड़क पर आ गया और उसे बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन सामने आ रहे आटों से टकराकर दोनों वाहन पलट गए। इस हादसे में डेढ़ दर्जन लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज स्वास्थ्य केंद्र तेन्दूखेड़ा में चल रहा है। 6 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

लापरवाह एवं अनुपस्थित शिक्षक को वेतन देने पर प्रभारी प्राचार्य निलंबित

सागर। दोपहर मेट्रो

स्कूल के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री में नियमों का पालन नहीं करने व विधालय में लगातार गैरहाजिर रहने वाले शिक्षक को वेतन देने वाले प्राचार्य को संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने निलंबित किया है। मिली जानकारी के अनुसार मप्र भंडार क्रय नियम 09 एवं प्रपत्र में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नहीं करने एवं सहायक शिक्षक द्वारा विद्यालय में लगातार अनुपस्थित पाये जाने पर भी वेतन देने पर सीएम राईज (संदीपनी विद्यालय) बांदरी के प्रभारी प्राचार्य देवेन्द्र कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया।

कमिश्नर कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार प्रभारी प्राचार्य मिश्रा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के लिए गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा विद्यालय के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री के क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम प्रावधान अनुसार प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नहीं किया गया। वर्ग 3 सहायक शिक्षक विज्ञान, दिव्यांश मिश्रा के विद्यालय में लगातार अनुपस्थित पाये जाने के पश्चात् भी प्रभारी प्राचार्य सीएम राईज (संदीपनी विद्यालय) बांदरी जिला सागर द्वारा दिव्यांश मिश्रा को वेतन भुगतान किया गया है। जांच समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर से प्राप्त अभिमत के उपरांत देवेन्द्र कुमार मिश्रा प्रभारी प्राचार्य सीएम राईज (संदीपनी विद्यालय) बांदरी जिला सागर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

बाणसागर समझौते पर उठ रहे सवाल

संभाग में उद्योगों को पानी आवंटन पर विवाद

शहडोल। दोपहर मेट्रो

बाणसागर परियोजना से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों और जल अधिकार से जुड़े जानकारों का आरोप है कि परियोजना से पूर्व ही सोन नदी के पानी के उपयोग की अनुमति कई निजी उद्योगों और प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांटों को दी जा रही है, जो मूल समझौते की भावना के विपरीत है।

ज्ञात हो कि बाणसागर परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर त्रिपक्षीय करार हुआ था। इस करार में स्पष्ट प्रावधान बताया जाता है कि सोन नदी के जल का बड़ा हिस्सा–लगभग 80 प्रतिशत–परियोजना और सिंचाई उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसे में यदि परियोजना के पूर्व या उससे अलग औद्योगिक उपयोग के लिए पानी आवंटित किया जाता है, तो यह तीनों राज्यों के साझा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सूत्रों के अनुसार शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों–अनूपपुर, शहडोल में कई औद्योगिक इकाइयों और संभावित ताप विद्युत परियोजनाओं को जल उपयोग की स्वीकृति दी गई है या प्रक्रिया में है। इससे आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि किसी भी प्रकार से त्रिपक्षीय समझौते में फेरबदल या उसकी मूल भावना से हटकर निर्णय लिए जा रहे हैं, तो इसकी पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उनका मत है कि बाणसागर परियोजना का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय सिंचाई, किसानों को पानी उपलब्ध कराना और तीनों राज्यों के बीच संतुलित जल बंटवारा सुनिश्चित करना था, न कि निजी उद्योगों को प्राथमिकता देना। इस पूरे मामले में परियोजना प्रबंधन और जल संसाधन विभाग से अपेक्षा की जा रही है कि वे त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें और यह बताएं कि उद्योगों को जल आवंटन किन नियमों और प्रावधानों के तहत किया गया है। यदि समझौते में कोई संशोधन हुआ है, तो उसकी प्रति भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। जल विशेषज्ञों का मानना है कि सोन नदी जैसे अंतरराज्यीय जल स्रोतों के मामले में पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मेट्रो एंकर | निगमायुक्त ने मधुकर शाह वार्ड से कुत्तों के टीकाकरण का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए

आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी, पुणे की एजेंसी को दिया टेंडर

सागर। दोपहर मेट्रो

नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों की रोकथाम के लिए बधियाकरण एवं टीकाकरण के लिए बुलाए गए टेंडर से पुणे की यारा फाउंडेशन एनजीओ को ठेका दिया गया है। फाउंडेशन की टीम ने निगमायुक्त राजकुमार खत्री की मौजूदगी में प्रस्तुतिकरण दिया।

फाउंडेशन के डॉ. पुष्पेंद्र प्रजापति एवं उनकी टीम के सदस्यों ने बताया कुत्तों का बधियाकरण एवं उनका उपचार वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। जिन स्थानों से मेल एवं फीमेल कुत्तों को पकड़ेंगे उनकी नसबंदी एवं एंटी रेबीज टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जिससे उनकी संख्या सीमित रहेगी। कुत्तों को पकड़ने में लोहे के जाल का उपयोग नहीं किया जाएगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं एंटी रैबीज में यारा फाउंडेशन मई 2022 में पंजीकृत एनजीओ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो वर्ष

2023 से सागर में अनेक एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं मेडिकल कैंप कर एंटी रैबीज टीकाकरण अभियान में 500 से ज्यादा सर्जरी कर चुका है। डॉ. प्रजापति को 2 हजार से ज्यादा सर्जरी का अनुभव है। सागर नगर निगम क्षेत्र में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम सीएनवीआर प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा। यह कार्यक्रम एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 के अनुसार किया जाएगा और एक स्थानीय एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी, जो कार्यक्रम की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। कुत्तों को किसी क्षेत्र से पकड़ने से पहले नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों एवं स्वयंसेवकों की सहायता से घोषणा/ परामर्श किया जाएगा तथा किसी क्षेत्र में कम से कम 70 प्रतिशत कुत्तों की नसबंदी करने के बाद ही अगले क्षेत्र में बधियाकरण की कार्रवाई की जाएगी। कुल नसबंदी किए गए कुत्तों में से कम से कम 60 प्रतिशत मादा होंगी। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने फाउंडेशन द्वारा दी गई प्रस्तुति देखने के बाद कहा सबसे पहले मधुकरशाह वार्ड से कुत्तों के बधियाकरण का कार्य शुरू करें। क्योंकि वहां पर आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया था। इसके बाद अन्य जगहों पर भी लगातार काम किया जाएगा।

ट्राफी को पैरों तले रखने वाली आस्ट्रेलियाई टीम टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर

3 साल बाद कुदरत का निजाम कंगारुओं पर पड़ा भारी

कैंडी (पल्लेकेले) , एजेंसी

साल 2026 चल रहा है, 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप कप 19 नवंबर 2023 को भारत को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हराकर जीता था। उस वर्ल्ड कप में भारत को हराने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श की एक तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें उनके पैरों के तले उस साल का वनडे वर्ल्ड कप था। मार्श की उस तस्वीर पर खूब बवाल हुआ था। तब उन्होंने उस वायरल तस्वीर पर रिएक्शन दिया था। मार्श ने तब यह पूछे जाने पर कहा कि क्या वह ऐसा दोबारा करेंगे? तब उन्होंने कहा- हां शायद, सच कहूं तो। उस फोटो में किसी का भी अपमान करने का इरादा नहीं था। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा है, सोशल मीडिया पर भी ज्यादा कुछ नहीं देखा है, हालांकि सब कह रहे हैं कि यह वायरल हो गई है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

उस घटना के बाद आज (मंगलवार) तारीख 17 फरवरी है, जहां तब की वनडे वर्ल्ड चैम्पियन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है। फिर इस बात पर सोशल मीडिया पर बज्ज है कि आखिरकार ऑस्ट्रेल?या ने जो बेकदरी उस वर्ल्ड कप की कर डाली थी, उसका बदला उसे इस टी20 कप में मिला है। अब इसी पूरे घटनाक्रम पर कुछ फैन्स कह रहे हैं, वो कहते हैं ना जब आप जीतें, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। खास बात यह है कि कंगारू टीम के बाहर होने का अपडेट भी आयरलैंड और ज?म्बाब्वे के बीच हुए रद्द मैच के बाद से आया।

एक-एक अंक ने बदल दी तस्वीर

मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों आयरलैंड और जिम्बाब्वे को एक-एक अंक मिला। इस साझा अंक के साथ जिम्बाब्वे के कुल पांच अंक हो गए, जो उसे सुपर-8 में पहुंचाने के लिए पर्याप्त साबित हुए। अब जिम्बाब्वे 26 फरवरी को चेन्नई में अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में भारत से भिड़ेगा। जिम्बाब्वे सुपर-8 में पहुंचने वाली सातवीं टीम बनी और उसने ग्रुप-ब1 को पूरा किया, जिसमें पहले से साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमें शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें बारिश में बह गईं

बारिश से पहले समीकरण यह था कि ऑस्ट्रेलिया की राह तभी बनती, जब जिम्बाब्वे अपने बचे दोनों मैच हारता। लेकिन मौसम ने ऐसा होने का मौका ही नहीं दिया और लगातार बारिश ने उनके अभियान पर विराम लगा दिया। मंगलवार को यह मुकाबला पल्लेकेले इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के कारण टॉस में देरी हुई मैदान लंबे समय तक कवर्स से ढका रहा और गीला आउटफील्ड खेलने लायक नहीं बन पाया। अंततः बिना एक भी गेंद डाले मैच रद्द करने का फैसला लिया गया।

श्रीलंका पहले ही कर चुका था क्वालिफाई

ग्रुप बी में शीर्ष पर चल रही श्रीलंका पहले ही सुपर-8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। ऐसे में यह मुकाबला जिम्बाब्वे और आयरलैंड के लिए 'करो या मरो' जैसा था। जिम्बाब्वे अब 19 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगा, लेकिन सुपर-8 का टिकट वह पहले ही सुनिश्चित कर चुका है। कुल मिलाकर एक भी गेंद खेले बिना मिला यह परिणाम जिम्बाब्वे के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक अंत लेकर आया। अब सुपर-8 में जिम्बाब्वे के सामने असली चुनौती होगी, जहां उसे भारत जैसी दिग्गज टीम से शुरुआत करनी है।

महिला टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी

वनडे सीरीज के लिए ओपनर प्रतिका रावक की टीम में वापसी, चोट से उबर कर 4 महीने बाद दिखेंगी मैदान में

इस्लामाबाद , एजेंसी

टीम इंडिया के लिए एक खुशखबरी है। धाकड़ ओपनर प्रतिका रावल फिट हो चुकी हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला वनडे टीम में शामिल किया गया है। फिलहाल टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। इसके बाद 24 फरवरी से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। प्रतिका पिछले साल अक्तूबर में चोटिल हुई थीं। वनडे महिला वनडे विश्वकप के बीच में टूर्नामेंट से बाहर हुई थीं। हालांकि, उनकी कई शानदार पारियों ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था।

प्रतिका रावल 26 अक्तूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोट लगी थी। बांग्लादेश के खिलाफ खेलते समय उनके दाहिने टखने और घुटने में चोट लग गई थी। बारिश के कारण वह मैच पूरा नहीं हो सका था। चोट के चलते वह टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में भी नहीं खेल पाईं। प्रतिका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए चुनी जा चुकी हैं। वह पहली बार टेस्ट खेलती दिख सकती हैं।

बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि महिला चयन समिति ने चल रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे के तहत होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के

वर्ल्ड के दौरान चोटिल हुई थी प्रतिका

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, %प्रतिका रावल ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है और अक्तूबर में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान लगी अपनी टखने की चोट से पूरी तरह ठीक हो गई हैं। अपनी चोट से पहले, 24 साल की ओपनिंग बल्लेबाज वनडे विश्व कप में इंडिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मर में से एक थीं और टीम के लिए 308 रन बनाकर दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिसमें एक सेंचुरी और एक हाफ-सेंचुरी शामिल है। रावल ने दिसंबर 2024 में अपना वनडे डेब्यू किया और तुरंत सफलता भी हासिल की। 24 पारियों में, उन्होंने 50.45 की एवरेज और 82.83 के स्ट्राइक रेट से 1110 रन बनाए हैं और टॉप ऑर्डर में बड़ा योगदान दिया है। उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें इस महीने की शुरुआत में अपना पहला बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था।

ब्रिस्बेन में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जबकि बाकी दो मैच होबार्ट में होंगे। इस समय दोनों टीमों के बीच टी-20 सीरीज चल रही है, जिसमें भारतीय महिला टीम 1-0 से आगे है। टी20 सीरीज 21 फरवरी को समाप्त होगी। वहीं, वनडे सीरीज के बाद छह मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा छेत्री (विकेट कीपर), काश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, प्रतिका रावल।

रणजी सेमीफाइनल में शमी का कहर

8 विकेट लेकर चयनकर्ताओं को दे दिया करारा जवाब

नई दिल्ली , एजेंसी

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 17 फरवरी को कल्याणी के बंगाल क्रिकेट एकेडमी मैदान में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए शमी ने जम्मू-कश्मी की पहली पारी के दौरान आठ विकेट झटककर सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, बंगाल की स्थिति खराब है जम्मू-कश्मीर को दूसरी पारी में जीतने के लिए 126 रन बनाने हैं। बंगाल क्रिकेट ग्राउंड पर शमी ने रफ्तार, सटीक लाइन-लेंथ और अनुभव का बेहतरीन नमूना पेश किया। पहली पारी के 59वें ओवर में उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज कनहैया वधावन को कैच आउट कर अपना पांचवां विकेट पूरा किया। इसके बाद उनका जोशीला जश्न साफ दिखा कि वह किस आत्मविश्वास में गेंदबाजी कर रहे हैं। मैच में कुल आठ विकेट लेकर शमी ने साबित किया कि घरेलू क्रिकेट में उनका फॉर्म लगातार निखर रहा है। 35 वर्षीय शमी इस रणजी सीजन में अब तक सात मैचों में 38 विकेट ले चुके हैं, जिसमें तीन बार पांच विकेट हॉल शामिल है। पिछले महीने सर्विसेज के खिलाफ भी उन्होंने 5/51 का बेहतरीन प्रदर्शन किया था।

क्या होगी टीम इंडिया में वापसी?

शानदार प्रदर्शन के बावजूद शमी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और 2026 टी20 विश्व कप की टीम में जगह नहीं बना सके। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वह भारतीय टीम से बाहर हैं और बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खो चुके हैं। हालांकि, मौजूदा फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब 2026 में भारत के सामने बड़े टेस्ट मुकाबले हैं। रणजी ट्रॉफी के बाद शमी आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स की ओर से खेलते नजर आएंगे, लेकिन जिस लय में वह हैं, उससे साफ है कि उनका लक्ष्य सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं, बल्कि टीम इंडिया में जोरदार वापसी है।

मनोरंजन **बॉलीवुड का कोना**

अनुपमा ने उठाया मर्दों के साथ होने वाले शोषण का मुद्दा

रुपाली बोलीं- औरतें नहीं, पुरुष भी होते शिकार

टीवी शो अनुपमा में एक बार फिर समाज के अनदेखे और संवेदनशील मुद्दे को उठाता नजर आएगा। शो में मेकर्स ने पुरुषों के साथ होने वाले भावनात्मक और मानसिक उत्पीड़न को दिखाया है। यह दिखाता है कि घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। कहानी में मोती बा की भतीजी कीर्ति को बाहर से एक आदर्श पत्नी दिखाया गया है, जो अपने पति कपिल की अच्छे से देखभाल करती नजर आती है। लेकिन बंद कमरे में वह कपिल को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, ब्लैकमेल और टॉर्चर करती है। कपिल इस सबके बारे में किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि समाज में पुरुषों को पीड़ित मानने की सोच

कम है और कीर्ति ने अपनी परफेक्ट इमेज इतनी मजबूत बना रखी है कि उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। अनुपमा, जो हमेशा सही के साथ खड़ी रहती हैं, कीर्ति के व्यवहार में कुछ गड़बड़ियां नोटिस करती हैं। वह कपिल के दर्द को समझती हैं और सिर्फ इसलिए कीर्ति का समर्थन नहीं करतीं क्योंकि वह एक महिला है। अनुपमा सच की तलाश में रहती हैं और परिवार के सामने कीर्ति के असली चेहरे को बेनकाब करने में जुट जाती है।

अनुपमा ने की मेकर्स की तारीफ

यह एपिसोड मैसेज देता है कि दुर्व्यवहार जेंडर से परे है और पीड़ित किसी भी जेंडर का हो सकता है। शो की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने इस थीम पर खुशी जताते हुए मेकर्स की तारीफ की। उन्होंने कहा, अनुपमा के मेकर्स की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे टॉपिक उठाए जो समाज में अभी भी टैबू हैं। वह अनुपमा को अक्सर उन मुद्दों के लिए आवाज बनाते हैं, जो दबी रहती हैं। मुझे राजन शाही, दीपा शाही और डीकेपी प्रोडक्शंस के इस विजन का हिस्सा बनने पर गर्व है। रुपाली ने आगे कहा, अनुपमा हमेशा समाज के मुद्दों पर बोलती आई है, चाहे किसान, दिवाली पर एडजस्टमेंट, आवारा जानवरों को खाना, गाय की सेवा या कुत्तों को रोटी खिलाना हो। अब यह ट्रैक पुरुषों के साथ गलत व्यवहार, घरेलू हिंसा और पति के शिकार होने जैसे विषयों पर बात कर रहा है। यह मेरे लिए बहुत दिल को छूने वाला और गर्व की बात है कि मुझे मेकर्स की इस सोच को आवाज देने का मौका मिला।

मेट्रो बाजार

एआई से 2050 तक खत्म हो सकती हैं पारंपरिक नौकरियां

नई दिल्ली। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी और वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला ने मंगलवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2050 तक लोगों को शायद पारंपरिक नौकरियों की जरूरत ही न पड़े। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यह रोजगार की प्रकृति को पूरी तरह बदल सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बोलते हुए खोसला ने कहा कि आने वाले दशकों में एआई सिस्टम और ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम हो जाएंगे, जिससे नौकरियों का भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि 2025 तक यह साफ दिखने लगेगा कि पारंपरिक रोजगार ढांचा तेजी से बदल रहा है। सिलिकॉन वैली के निवेशक खोसला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी संख्या में व्हाइट-कॉलर नौकरियों को खत्म कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि आईटी सर्विस और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियां अगले पांच वर्षों में लगभग पूरी तरह गायब हो सकती हैं। उन्होंने दोहराया कि 2030 तक आउटसोर्सिंग उद्योग खत्म हो सकता है। खोसला के मुताबिक, भारत में अब भी कई लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि एआई आईटी सेक्टर पर बड़ा असर डालेगा, लेकिन तकनीक की तेज प्रगति उन उद्योगों को भी प्रभावित करेगी, जो अब तक देश की आर्थिक वृद्धि का आधार रहे हैं।

खोसला ने बड़ी कंपनियों में 15 से 20 साल तक लगातार काम करने की प्रवृत्ति की भी आलोचना की। उनका कहना है कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में लंबे समय तक एक ही संस्था में काम करने से पेशेवरों की अनुकूलन क्षमता कम हो सकती है। ऐसे लोग बदलते उद्योग वातावरण में कम लचीले हो जाते हैं। हालांकि, चेतावनियों के बीच खोसला ने भारत की एआई पहल की तारीफ भी की।

भारत में रजिस्टर्ड ड्रोन की संख्या 38,500 के पार 39,000 से अधिक प्रमाणित रिमोट पायलट

नई दिल्ली । भारत में ड्रोन इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में पंजीकृत ड्रोन की संख्या 38,500 के पार पहुंच गई है और देश में फरवरी 2026 तक डीजीसीए-प्रमाणित रिमोट पायलटों की संख्या 39,890 हो गई है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ड्रोन संचालन और रखरखाव के लिए 240 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, जो कुशल जनशक्ति तैयार कर रहे हैं। सरकार के बयान के मुताबिक, ड्रोन का बढ़ता उपयोग एक मजबूत इकोसिस्टम को दर्शाता है, जिसमें निर्माता, सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट डेवलपर, सेवा प्रदाता, प्रशिक्षण संस्थान, प्रमाणित पायलट, स्टार्टअप, शोध संस्थान और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। यह पूरा ढांचा एक समान नियामक व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। ड्रोन अब कृषि, भूमि और संपत्ति सर्वेक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, आपदा आकलन और सरकारी सेवाओं में सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और काम की सटीकता बढ़ रही है। स्वामित्व योजना के तहत अब तक 3.28 लाख गांवों का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है और 31 राज्यों के 1.82 लाख गांवों में 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ड्रोन क्षेत्र अब पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर एक मुख्यधारा और नवाचार-आधारित सेक्टर बन चुका है, जिसे प्रगतिशील नीतियों और वित्तीय प्रोत्साहन का समर्थन मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1,094 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वितरित किए गए हैं।

भरोसेमंद व्यक्ति ने दिया था धोखा, ऋचा चड्ढा ने बयां किया करियर का शुरुआती अनुभव,

अभिनेत्री और निर्माता ऋचा चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत के दौरान एक कड़वे अनुभव को साझा किया है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति पर वह बहुत भरोसा करती थीं, उसने उनके हितों के खिलाफ काम किया और उन्हें धोखा दिया था।

ऋचा ने बताया कि इस घटना से उन्हें यह सबक मिला कि हर कोई आपका ध्यान नहीं रख सकता या आपके बारे में नहीं सोच सकता। ऋचा ने कहा, ÷अपने करियर की शुरुआत में मुझे यह कड़वा सबक मिला कि हर कोई आपका इतना ध्यान नहीं रखता। मैं भोली थी। कुछ लोग थोड़े से अंतर से भी खतरा महसूस करते हैं और नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाएं या उनकी स्पॉटलाइट छीन लें। यह अनुभव उनके लिए काफी परेशान करने वाला था, लेकिन इससे उन्होंने अपनी पसंद का बचाव करना और सही लोगों पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह उनसे संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। आम धारणा है कि बड़े एक्टर्स से अप्रोच करना मुश्किल

होता है, लेकिन ऋचा ने इसे गलत बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ÷एक सोच है कि हमसे संपर्क करना कठिन है, लेकिन यह सच नहीं। मेरे लिए सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट, सच्ची राइटिंग और कहानी का असर मायने रखता है। मैं हमेशा सही कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं। ऋचा ने शुरुआती दिनों में कम आंके जाने की बात भी कही। वह चाहती हैं कि इंडी क्रिएटर्स बिना झिझक के अच्छे रोल और कहानियों के लिए संपर्क करें।

81 हजार करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एनजीटी से मंजूरी

» सरकार बनाएगी एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर प्लांट

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की 6 सदस्यों वाली स्पेशल बेंच ने 81,000 करोड़ रुपये के ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा कि उन्हें प्रोजेक्ट को दी गई पर्यावरण मंजूरी में दखल देने का ' 'कोई अच्छा आधार'' नहीं मिला, क्योंकि प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी में ' 'काफी सुरक्षा उपाय'' थे। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने ' 'प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व'' और उन मुद्दों पर भी ध्यान दिया, जिनसे एनजीटी के 2023 के आदेश के अनुसार, प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस पर फिर से विचार करने के लिए बनाई गई हाई-पावर्ड कमेटी ने निपटा था।

प्रोजेक्ट के लिए काटे जाएंगे 10 लाख पेड़

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 166 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मेगा प्रोजेक्ट में 130 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन का डायवर्जन और लगभग 10 लाख पेड़ों की कटाई शामिल है। सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट और एक 450-MVA गैस और सोलर पावर प्लांट का निर्माण करना चाहती है। केंद्र ने निकोबारी समुदाय की अपनी पुरखों की जमीन (जो 2004 की सुनामी में तबाह हो गई थी) से बेदखल होने और इकोलॉजिकल नुकसान की चिंताओं के बीच इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है।

न्यूज विंडो

बैडमिंटन कोर्ट में कारोबारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कारोबारी अमृत बजाज की अचानक मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। कारोबारी की मौत बैडमिंटन खेलते वक्त हुई। उनकी उम्र 57 साल की थी। ईदगाह भाठा निवासी अमृत बजाज अश्वनीनगर स्थित सोनकर बाड़ी के ओपन कोर्ट में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि दूसरे शॉट के दौरान शटल उठाने के लिए झुकते समय वे अचानक गिर पड़े।साथी खिलाड़ियों ने पहले उन्हें संभालने की कोशिश की। पानी के छींटे मारे गए और तौलिये से हवा दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तुरंत उन्हें रायपुरा स्थित जगन्नाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में वे सामान्य रूप से खेलते नजर आते हैं। पहला शॉट खेलने के बाद जैसे ही वे दूसरे शॉट पर झुकते हैं, अचानक गिर जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

एंट्री बंद हुई तो टूट गई उम्मीदें, परीक्षा से वंचित छात्रा ने की आत्महत्या

पटना। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। मसौढ़ी के खरजमा गांव की छात्रा ने परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। वह निर्धारित समय से मात्र 10 मिनट देरी से पहुंची थी। केंद्र पर सुबह 9 बजे एंट्री बंद कर दी गई थी। छात्रा 9:10 बजे पहुंची, लेकिन गेट नहीं खुला। काफी अनुरोध के बावजूद उसे प्रवेश नहीं मिला। हताश होकर वह घर लौट गई।बताया गया कि कोमल की परीक्षा बरनी स्थित केंद्र पर थी। वह सोमवार को ही रिश्तेदार के यहां महाराजचक गई थी। केंद्र उसके ठहरने के स्थान से करीब 6 किलोमीटर दूर था।एंट्री नहीं मिलने के बाद वह नदौल गई। वहां से ट्रेन में सवार हो गई। तरेगना और मसौढ़ी कोर्ट के बीच चलती ट्रेन से कूद गई।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना ने परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के मानसिक दबाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार में मातम का माहौल है। स्थानीय लोग भी सदमे में हैं।

ओला के फाउंडर भाविश को मिली बॉम्बे कोर्ट से राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और ष्टश्वह्र भाविश अग्रवाल के खिलाफ साउथ गोवा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन द्वारा जारी डिटेंशन ऑर्डर और वारंट पर रोक लगा दी। बता दें कि कंज्यूमर कमीशन ने अग्रवाल के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया था। कमीनशन ने कहा था कि पहले से नोटिस दिए जाने के बावजूद अग्रवाल पेश नहीं हुए। जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने कमीशन को नोटिस जारी किया और कहा कि पहली नजर में लगता है कि ऐसा वारंट जारी करके उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।हाई कोर्ट ने कहा, 'कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की स्कीम को देखने पर, जब मुआवजा देने का ऑर्डर पास हो जाता है और उसे एक्ट के सेक्शन 71 के तहत लागू करने की कोशिश की जाती है, तभी स्टेट कमीशन को एक्ट के सेक्शन 71 के तहत सिविल कोर्ट की तरह अपने ऑर्डर को लागू करने के लिए डिटेंशन वारंट जारी करने की पावर मिलती है। 'कोर्ट ने आगे कहा, 'कंज्यूमर फोरम या कमीशन के सामने किसी विवाद में किसी भी पार्टी को शिकायत की सुनवाई के दौरान ऐसा वारंट जारी करने की कोई पावर नहीं है '।

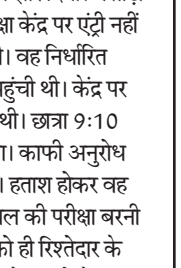

ईरान झुकने को तैयार नहीं, कहा- ऐसा मारेंगे कि उठेंगे नहीं

यूएस ने 24 घंटे में पश्चिम एशिया भेजे 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। पहले खबर आई कि अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत पश्चिम एशिया में तैनात किए हैं। जिसके बाद आशंका हुई कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब खबर आई है कि अमेरिका ने बीते 24 घंटे में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया भेजे हैं। इसे अमेरिका द्वारा ईरान के आसपास अपनी नौसैन्य और वायु सेना की तैनाती बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना को धमकी दी है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पर भी ऐसा हमला होगा कि वे दोबारा उठ नहीं पाएंगे।

ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में हो रही बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होनी है। बीते हफ्ते ही अमेरिका ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को पश्चिम एशिया में तैनात किया है। साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही पश्चिम एशिया में तैनात है। अब 50 से ज्यादा अतिरिक्त लड़ाकू विमान भेजने को अमेरिका द्वारा ईरान पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है।

खामेनेई ने दी धमकी

अमेरिका द्वारा सैन्य तैनाती बढ़ाने के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में अमेरिका को धमकी दी है। खामेनेई ने लिखा, 'अमेरिका द्वारा लगातार कहा जा रहा है उन्होंने ईरान की तरफ युद्धपोत भेजा है। बेशक एक युद्धपोत बेहद खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक है वो हथियार, जो युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है।'खामेनेई ने ईरान की परमाणु महत्वकांक्षा पर भी अपने विचार रखे। खामेनेई ने लिखा 'यह बात कि परमाणु ऊर्जा हमारा हक है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की गाइडलाइंस में भी शामिल है।

राष्ट्रपति लेंगी सलामी

आज गरजेंगे मिग-29के एलसीए तेजस और पी-8आई टोही विमान

विशाखापत्तनम। सिटी ऑफ डेस्टिनी कहे जाने वाले विशाखापत्तनम के समुद्री तट पर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) के जरिये दुनिया को भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का परिचय देंगी। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार शाम विशाखापत्तनम पहुंची।

मुर्मू बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर समुद्र के बीच खड़े बेड़े का निरीक्षण करेंगी। इस रिव्यू में भारतीय नौसेना के साथ-साथ मित्र देशों के कुल 71 जहाज और पनडुब्बियां शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर फ्लाई-पास्ट कर राष्ट्रपति को सलामी देंगे। आकाश में मिग-29के, एलसीए तेजस, पी-8आई टोही विमान और सी-किंग हेलिकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। दुनिया के सबसे घातक समुद्री कमांडो माने जाने वाले नौसेना के मार्कोस समुद्र के बीच विशेष युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे।

कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं

कोलकाता, एजेंसी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पुरुष पर महिला की तरफ से लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अदालत ने कहा है कि अगर शादी नहीं हो पाती है और रिश्ता टूट गया है, तो सिर्फ इसलिए ही आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि शुरुआत से ही धोखा देने का इरादा होना चाहिए था। जज ने आगे कहा कि जिस तरह से दोनों (महिला और पुरुष) व्यवहार कर रहे थे, उससे दोनों की आपसी सहमति के संकेत मिल रहे थे।जानकारी के अनुसार, बीते सोमवार (16 फरवरी) को हाईकोर्ट ने

आरोपी के खिलाफ दर्ज केस रद्द कर दिया। शख्स पर आरोप थे कि उसने शादी का वादा कर महिला के साथ दुष्कर्म किया और जबरन गर्भपात भी कराया है। इस मामले में जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की बेंच ने कहा कि जब दोनों साथ में घूमे और पति पत्नी की तरह रहे। ऐसे में यह आपसी सहमति दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआत से ही धोखा देने या गलत इरादा होना चाहिए था, इसके तहत महिला को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया हो।

होली पर घर जाना हुआ आसान: रेलवे चलाएगा 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर तैनात रहेंगे डॉक्टर

नई दिल्ली, एजेंसी

रंगों के त्योहार होली की खुमारी अभी से लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है, लेकिन घर जाने की जद्दोजहद ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी थी। दिल्ली-एनसीआर से यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाली लगभग सभी नियमित ट्रेनों में 'नो रूम' के बोर्ड लग चुके हैं और वेटिंग लिस्ट आसमान छू रही है। यात्रियों की इसी टेंशन को दूर करने के लिए उत्तर रेलवे ने इस बार कमर कस ली है। इस साल रिकॉर्ड तोड़ 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है, ताकि हर मुसाफिर अपनों के साथ होली का आनंद ले सके।आंकड़ों की मानें तो इस साल रेलवे ने पिछले साल के मुकाबले ट्रेनों की संख्या में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। जहां पिछले साल 250 विशेष ट्रेनें पटरी पर उतरी थीं, वहीं इस बार यह आंकड़ा 300 के पार जाएगा।

सुरक्षा के साथ सेहत का भी ख्याल

सफर की आपाधापी में यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। स्टेशन परिसर में ही यात्रियों को प्राथमिक उपचार मिल सकेगा और आपात स्थिति के लिए रेलवे अस्पताल में 30 बेड भी रिजर्व रखे गए हैं।

मेट्रो एंकर

सिंधु जल संधि समझौते के निलंबित होने के बाद शाहपुर कंडी बांध का काम लगभग पूरा

पाक को दोहरा झटका, अब रावी का भी पानी रोकेगा भारत

नई दिल्ली, एजेंसी

सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद अब भारत पाकिस्तान को दोहरा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल भारत सरकार रावी नदी के भारत के हिस्से के जल को भी पाकिस्तान जाने से रोकने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो गर्मी के मौसम में पाकिस्तान का जल संकट गहरा सकता है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और यह परियोजना पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।

दरअसल सिंधु जल संधि समझौते के निलंबित होने के बाद पंजाब-जम्मू कश्मीर की सीमा पर बन रहे शाहपुर कंडी बांध के काम में तेजी आई है और अब यह प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राना ने यह जानकारी दी। राना ने ये भी कहा कि जब शाहपुर कंडी बांध का काम पूरा हो जाएगा तो उसकी मदद से रावी नदी के भारत के हिस्से के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान की तरफ बहने से भी रोका जा सकेगा। रावी नदी के रोके गए अतिरिक्त पानी को सूखा प्रभावित कठुआ और सांबा जिलों की तरफ डायवर्ट किया जा सकेगा। शाहपुर कंडी बांध का काम 31 मार्च तक पूरा हो सकता है। जावेद अहमद राना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'पाकिस्तान को जाने वाला अतिरिक्त पानी रोका जाएगा और ये रोका भी जाना चाहिए। कठुआ और सांबा जिले सूखाग्रस्त है और ये प्रोजेक्ट हमारी प्राथमिकता है, जो कंडी इलाके में बनाया जा रहा है।'

शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट

अभी रावी नदी का भारत के हिस्से का पानी भी बहकर पाकिस्तान चला जाता है। अब शाहपुर कंडी बांध की मदद से इस पानी को रोककर इसे पंजाब और जम्मू कश्मीर के सूखाग्रस्त इलाकों को दिया जाएगा। शाहपुर कंडी बांध परियोजना की योजना साल 1979 में रावी नदी के भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। साल 1982 में इस बांध की आधारशिला पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने रखी। हालांकि पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवाद के चलते इसका निर्माण कार्य रुक गया। साल 2008 में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया। इस बांध को बनाने की लागत करीब 3394 करोड़ रुपये है, जिसमें से पंजाब सरकार ने 2694 करोड़ और बाकी 700 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिए हैं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रसलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564